सीपीसीबी की रिपोर्ट : दिल्ली की हवा चार महीने बाद फिर जहरीली, एनसीआर में ग्रैप-1 लागू

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

लोकशक्ति

एक्टर पंकज धीर का मुंबई में निधन, महाभारत में कर्ण का रोल निभाकर हुए थे फेमस

RNI Regn. No.7789/1964 | वर्ष-61 > अंक - 288 | रायपुर | गुरूवार 16 अक्टूबर 2025 विक्रम संवत 2082 | पृष्ठ 8 > मूल्य : 2 रू. | डाक पंजीयन : C.G./RYP DN/71/2023-25

नक्सलवाद पर ऐतिहासिक जीत! 'सबसे प्रभावित' जिले घटकर 3 हुए!

देश में माओवादी खतरा सिर्फ 11 जिलों में सिमटा

एजेंसी

केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने देश में दशकों से जारी वामपंथी उग्रवाद की चुनौती के खिलाफएक बड़ी सफलता का दावा किया है. बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, माओवादी हिंसा से प्रभावित जिलों की संख्या में ऐतिहासिक कमी आई है और यह अब पहले के 18 जिलों से घटकर केवल 11 जिलों तक सीमित रह गई है. यह घोषणा भारत के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाती है, जहां दशकों के संघर्ष के बाद सरकारी नीतियां और कार्रवाई अब स्पष्ट परिणाम दिखा रही हैं.

मंत्रालय ने बताया कि इस बड़ी सफलता के पीछे मुख्य कारण राष्ट्रीय कार्य योजना और नीति है, जिसने उग्रवाद से निपटने के लिए एक बहुआयामी और व्यापक दृष्टिकोण अपनाया. इस रणनीति में तीन मुख्य स्तंभ शामिल हैं: प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती और कठोर कार्रवाई को बढ़ाना, स्थानीय लोगों के लिए विकास कार्यों को तेज करना, और उग्रवादियों को मुख्यधारा में वापस लाने के लिए एक प्रभावी आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति लागू करना.

आंकड़ों में सबसे अधिक राहत की बात 'सबसे अधिक प्रभावित' जिलों की श्रेणी में दर्ज की गई है. पहले इस श्रेणी में छह जिले शामिल थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर केवल तीन रह गई है. गृह मंत्रालय के अनुसार, ये तीनों जिले अब केवल छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्गम बस्तर संभाग तक सीमित हैं, जिनमें बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर शामिल हैं. यह भौगोलिक सिकुड़न यह दर्शाती है कि माओवादी गतिविधियाँ अब भारत के एक अत्यंत संकीर्ण और सीमित क्षेत्र तक सिमट गई हैं, जिससे सुरक्षा बलों को अपने अभियान को और अधिक केंद्रित करने में सहायता मिलेगी.

यह सकारात्मक खबर ठीक उसी दिन आई है जब माओवादी आंदोलन के लिए एक और बड़ा झटका लगा. महाराष्ट्र में सीपीआई (माओवादी) के एक वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल राव, जिसे संगठन में भुपाती के नाम से जाना जाता था, ने 60 अन्य कैडरों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया. एक उच्च-स्तरीय नेता और इतने बड़े समूह का एक साथ आत्मसमर्पण करना यह स्पष्ट संदेश देता है कि उग्रवादी समूह के भीतर अब न केवल निराशा बढ़ रही है, बल्कि सरकार की आत्मसमर्पण नीतियां भी उन्हें मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित कर रही हैं. मल्लोजुला राव जैसे प्रमुख कैडरों का आत्मसमर्पण सुरक्षा एजेंसियों को महत्वपूर्ण खुफ़िया जानकारी प्रदान करता है, जिससे शेष बचे माओवादी समूहों के खिलाफअभियानों को और अधिक सटीक बनाया जा सकता है.

वामपंथी उग्रवाद, जिसे आमतौर पर नक्सलवाद कहा जाता है, ने 2000 के दशक में देश के लगभग 100 से अधिक जिलों में अपना प्रभाव फैला लिया था, जिससे इन क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचागत विकास लगभग ठप हो गया था और स्थानीय आदिवासियों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ था. हिंसा, जबरन वसूली और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना इस चुनौती का मुख्य अंग था.

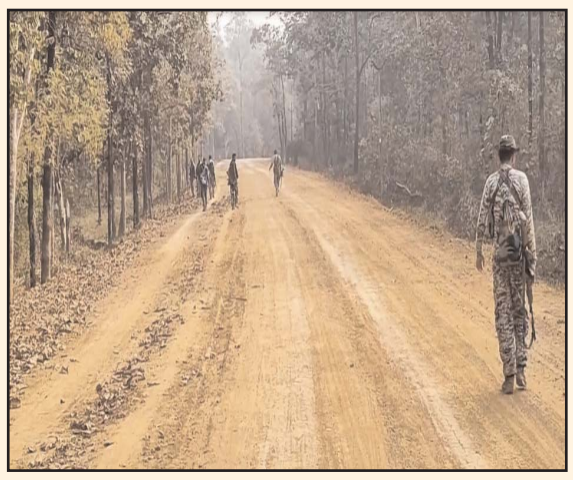

2013 तक थे 126 जिले नक्सल प्रभावित

बीते 2013 तक 126 जिले ऐसे थे जहाँ नक्सलवाद की पहुंच थी। आम लोगों में माओवादी विचारधारा के खोखलेपन को उजागर किया गया। इसके साथ ही माओवादियों से मुक्त किए गए इलाकों में बुनियादी ढांचे का तीव्र विकास और कल्याणकारी योजनाओं को पूरी तरह से लागू कराया गया, ताकि वहां की जनता दोबारा माओवादियों के दुष्प्रचार में नहीं फंसे। इसके साथ थी एनआइए और ईडी ने उनकी फंडिंग को पूरी तरह से रोकने का काम किया। सबसे बड़ी बात यह कि माओवादी समस्या से निपटने में राज्यों एवं केंद्र के बीच बेहतर समन्वय बनाते हुए खासतौर पर सीमावर्ती जिलों में संयुक्त टीमों का गठन किया गया।

कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में सीबीआई ने मारा छापा, अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी मामले में तीन गिरफ्तार

नई दिल्ली । केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड केस में सोमवार को कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई सीबीआई के ऑपरेशन चक्र-5 के तहत की गई, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करना है। इस दौरान एजेंसी ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने यह मामला गृह मंत्रालय (एमएचए) के अंतर्गत साइबर समन्वय केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर दर्ज किया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि देशभर के हजारों लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया था। आरोप है कि यह गिरोह सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों को ऑनलाइन निवेश और पार्ट-टाइम जॉब के झूठे वादों से फंसाकर उनसे भारी रकम वसूलता था। जांच से पता चला है कि इस नेटवर्क में भारतीय और विदेशी दोनों नागरिक शामिल थे।

योगी का कड़ा संदेश:

त्योहारों में शांति भंग करने वालों की जगह सिर्फ जेल में होगी

एजेंसी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को चेतावनी दी कि त्योहारों के जश्न में खलल डालने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत जेल भेज दिया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार 1 करोड़ 86 लाख उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को दिवाली उपहार के रूप में मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान कर रही है, जिससे उनकी सरकार का महिलाओं के कल्याण और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित होने की बात दोहराई जा रही है।

सभा को संबोधित करते हुए, सीएम योगी ने कहा कि अगर कोई भी इस त्योहार के आनंद और उत्साह को बाधित करने की कोशिश करेगा, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी; चाहे वे कोई भी हों, उन्हें बिना देर किए सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। त्योहारों और समारोहों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाना चाहिए। पिछले आठ वर्षों में, उत्तर प्रदेश में हर समुदाय के सभी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए गए हैं... यह अब दंगाइयों

के आगे झुकने वाली सरकार नहीं है। मुफ़्त रसोई गैस सिलेंडर वितरण कार्यक्रम में लाभार्थियों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सहायता प्राप्तकर्ताओं को बधाई दी और अपने कैबिनेट सहयोगियों सुरेश खन्ना, दिनेश शर्मा, संजय सेठ और महापौर सुषमा खरकवार का नाम लिया। उन्होंने दिवाली से पहले ÷राज्य के 1 करोड़ 86 लाख लाभार्थियों÷ को मुफ़्त सिलेंडर वितरण को दिवाली का तोहफ़ा बताया और 2021 में होली और दिवाली के अवसर पर साल में दो बार मुफ़्त रसोई गैस उपलब्ध कराने के सरकार के फ़ैसले को रेखांकित किया।

दिवाली-छठ पर रेलवे का बड़ा फैसला, इन 5 बड़े स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद

नई दिल्ली दीपावली और छठ पूजा के त्योहारों पर यात्रियों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रेलवे ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आज से यानी 15 अक्टूबर से दिल्ली और गाजियाबाद के पांच प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध 28 अक्टूबर तक लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही प्लेटफॉर्म पर प्रवेश की अनुमति होगी।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल और गाजियाबाद रेलवे स्टेशनों के लिए लिया गया है। इस अवधि में टिकट काउंटरों के साथ-साथ मोबाइल ऐप (UTS) और ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनों (ATVM) से भी प्लेटफॉर्म टिकट जारी नहीं किए जाएंगे।

अधिकारियों ने बताया कि त्योहारी सीजन में यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा हो जाता है। ऐसे में यात्रियों को छोड़ने आने वाले परिजनों की वजह से प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक भीड़ बढ़ जाती है, जिससे व्यवस्था बनाए रखने में मुश्किल होती है। इसी भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने और केवल वास्तविक यात्रियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

बिहार चुनाव : भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, मैथिली को अलीनगर सीट से टिकट

संवाददाता

पटना - बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी तैयारी तेज कर दी है। पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा रही है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें लोक गायिका मैथिली ठाकुर का भी नाम है।

एक दिन पहले प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी और दूसरे दिन यानी बुधवार को भाजपा ने उन्हें अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतार दिया। पार्टी की दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। भाजपा की दूसरी लिस्ट

के अनुसार, अलीनगर से मैथिली ठाकुर, हायाघाट से राम चंद्र प्रसाद, मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार और गोपालगंज सीट से सुभाष सिंह को टिकट मिला, जबकि बनियापुर से केदार नाथ सिंह, छपरा से छोटी कुमारी, सोनपुर से विनय कुमार सिंह और रोसड़ा से बीरेंद्र कुमार चुनाव मैदान में हैं। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से डॉ0 सियाराम सिंह, अगिआंव से महेश पासवान, शाहपुर से राकेश ओझा और बक्सर से रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को टिकट मिला। एक दिन पहले भाजपा ने 71 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में दोनों डिप्टी सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम समेत बिहार के कई मंत्रियों को टिकट दिया गया है। पार्टी ने बताया कि इसमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, प्रेम कुमार, मंगल पांडे, कृष्ण कुमार, राम नारायण मंडल और नितिन नबीन का नाम शामिल हैं। भाजपा की ओर से बताया गया कि जहां उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे तो वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय से भाजपा के उम्मीदवार होंगे। इसके साथ ही, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद कटिहार से भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। साथ ही पार्टी ने कई मंत्रियों और विधायकों को उनकी परंपरागत विधानसभा सीट से टिकट दिया है।

बिहार चुनाव : जेडीयू ने 57 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की, चिराग पासवान की सीटों पर भी उतारे उम्मीदवार

पटना. बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल गरमाने लगा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने अपने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करके चुनावी मैदान में अपनी तैयारी का ऐलान कर दिया है. लेकिन इस लिस्ट ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है.

इस लिस्ट की सबसे दिलचस्प बात यह है कि JD ने उन चार सीटों पर भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, जिन पर एनडीए के सहयोगी दल और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी (रामविलास) अपना दावा ठोक रही थी. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जेडीयू का यह कदम चिराग पासवान पर दबाव बनाने की एक रणनीति हो सकती है।

रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में ब्राजील के उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के साथ बैठक की

पीआईबी

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 15 अक्टूबर, 2025 को नई दिल्ली में ब्राजील के उपराष्ट्रपति श्री गेराल्डो अल्कमिन से मुलाकात की। इस बैठक में ब्राजील के रक्षा मंत्री श्री जोस म्यूसियो मोंटेइरो फि ल्हो भी उपस्थित थे। नेताओं ने वर्तमान में जारी रक्षा संबंधी गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की और रक्षा उपकरणों के सह-विकास एवं सह-उत्पादन के अवसरों की खोज सहित संयुक्त कार्य के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की। भारत और ब्राज़ील के बीच गहरी रणनीतिक साझेदारी है। दोनों नेताओं ने संयुक्त अभ्यासों, प्रशिक्षण यात्राओं एवं सैन्य आदान-प्रदान को सशक्त बनाकर रक्षा सहयोग को और आगे बढ़ाने के अपने साझा संकल्प को पुष्टि की।

विदेश

शांति समझौते की उड़ी धज्जियां, हमास ने सरेआम 8 लोगों को घुटनों पर बिठाकर सिर में मारी गोली

ट्रंप की हमास को सीधी चेतावनी, 'हथियार डाल दो, वरना हम डलवा देंगे

वाशिंगटन , एजेंसी । गाजा में शांति स्थापित करने के प्रस्ताव पर सहमति बनने के अगले ही दिन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकी संगठन हमास को बेहद कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर हमास ने समझौते के तहत अपने हथियार नहीं डाले, तो अमेरिका उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर देगा, चाहे इसके लिए हिंसक तरीका ही क्यों न अपनाना पड़े।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ट्रंप से सवाल पूछा गया कि अगर हमास शांति प्रस्ताव की शर्त के मुताबिक हथियार डालने से इनकार करता है तो अमेरिका क्या करेगा? इस पर ट्रंप ने अपने चिर-परिचित अंदाज़ में जवाब देते हुए कहा,

उन्हें (हमास को) हथियार डालने ही होंगे। अगर वे खुद ऐसा नहीं करेंगे, तो हम उनसे हथियार डलवा देंगे। ट्रंप ने आगे दावा किया कि उनके करीबी सहयोगियों ने हमास के शीर्ष नेतृत्व से बात की है और संगठन ने हथियार छोड़ने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा, मैंने हमास से बात की है। मैंने कहा कि आप हथियार छोड़ने जा रहे हैं, ठीक है? उन्होंने कहा कि 'यस सर, हम सारे हथियार खत्म कर देंगे।' उन लोगों ने मुझसे यही कहा है। इसके बाद भी यदि वे हथियार नहीं छोड़ेंगे तो हम सख्ती से निपटेंगे और यह तरीका थोड़ा हिंसक भी हो सकता है। इसके साथ ही, राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि हमास को एक-एक बंधक को बिना शर्त रिहा करना होगा और मारे गए लोगों के सभी शवों को भी वापस सौंपना होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य-पूर्व मामलों के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और अपने दामाद जेरेड कुशनर को इस शांति प्रक्रिया की कमान सौंपी है। बताया जा रहा है कि विटकॉफ और कुशनर ने ट्रंप की सहमति से मिस्र के शर्म अल-शेख में हमास के शीर्ष नेताओं के साथ सीधी बातचीत की थी, जिसके बाद इस शांति प्रस्ताव का रास्ता साफ हुआ।

पाक-अफगानिस्तान के बीच फिर झड़प, कई टैंक हुए तबाह

दोनों ने चौकियां कब्जाने का किया दावा

काबुल एजेंसी । अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कुछ घंटों की शांति के बाद मंगलवार रात फिर से भीषण टकराव हुआ। यह झड़प पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम जिले में हुई, जहां पाकिस्तानी सैनिकों और अफगान तालिबान के बीच भारी गोलीबारी और टैंक युद्ध की खबर है। पाकिस्तानी सरकारी चैनल पीटीवी के अनुसार, अफगान तालिबान और 'फित्ना अल-खवारिज' ने बिना किसी उकसावे के गोलीबारी शुरू की, जिसके जवाब में पाकिस्तानी सेना ने पूरी ताकत से कार्रवाई की। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की चौकियां कब्जाने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि लड़ाई में दोनों तरफ के कई टैंक नष्ट

हुए हैं। इससे पहले इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव को सऊदी अरब और कतर की मध्यस्थता से अस्थायी रूप से शांत किया गया था। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोमवार को ही कहा था कि सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और किसी भी वक्त स्थिति बिगड़ सकती है। इसके कुछ ही घंटे बाद मंगलवार रात संघर्ष छिड़ गया।

पाकिस्तानी सूत्रों के अनुसार, जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान की कई चौकियों को भारी नुकसान हुआ और कुछ चौकियों से आग की लपटें उठती देखी गईं। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी हमले में तालिबान का एक टैंक भी नष्ट हुआ, जिसके बाद तालिबानी लड़ाके पीछे हटने को मजबूर हुए।

रक्षा सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना पूरी तरह हाई अलर्ट पर है और सीमा की हर इंच की रक्षा के लिए तैयार है। वहीं अफगानिस्तान समर्थित सोशल मीडिया हैंडल्स ने विपरीत दावा किया है। 'वॉर ग्लोब न्यूज' के अनुसार, अफगान तालिबान के एक वीडियो में उनके ड्रोन को पख्तूनख्वा के सीमावर्ती क्षेत्र में एक पाकिस्तानी सैन्य अड्डे पर विस्फोटक गिराते हुए दिखाया गया है। एक अन्य वीडियो में तालिबान को पाकिस्तानी पोस्ट पर हमला करते दिखाया गया है।

'अफगानिस्तान डिफेंस' नामक हैंडल ने दावा किया कि अफगान सैनिकों ने पाकिस्तान की उन जगहों को निशाना बनाया जहां से अफगानिस्तान के खिलाफ गतिविधियां चलती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, अफगान फोर्स अब पाकिस्तान में सक्रिय दाएश (ISIS-खुरासान) समूह के ठिकानों को भी निशाना बना रही है। इसी हमले में सात पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है।

अफगानिस्तान सरकार ने आधिकारिक रूप से पाकिस्तान से मांग की है कि वह ISIS-खुरासान के शीर्ष नेताओं को अफगानिस्तान को सौंपे। इनमें शहाब अल-मुहाजिर, अब्दुल हकीम तौहीदी, सुल्तान अजीज और सलाहुद्दीन रजब के नाम शामिल हैं। अफगानिस्तान का कहना है कि ये नेता पाकिस्तान में छिपे हैं और वहीं से अफगानिस्तान पर हमले की योजना बना रहे हैं।

वेनेजुएला के पास जहाज पर अमेरिकी हमला, ड्रग तस्करी कर रहे 6 लोग मारे गए : ट्रंप

वाशिंगटन एजेंसी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिका की सेना ने वेनेजुएला के तट के पास अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे एक जहाज पर हमला किया, जिससे उसमें सवार छह लोगों की मौत हो गई। ट्रंप ने यह जानकारी ट्रुथ सोशल पर दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, सितंबर से अब तक अमेरिका की ओर से वेनेजुएला के आसपास नशा तस्करी में शामिल संदिग्ध जहाजों पर किए गए सैन्य हमलों में कुल 27 लोगों की मौत हो चुकी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पुष्टि की थी कि यह जहाज नशे की तस्करी के लिए जाने-पहचाने समुद्री मार्ग पर जा रहा था और अवैध मादक पदार्थों के आतंकवादी नेटवर्क से जुड़ा था। इससे पहले, ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस को एक ज्ञापन भेजकर सूचित किया था कि अमेरिका अब उन ड्रग कार्टेलों के खिलाफ 'गैर-अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष' की स्थिति में है जिन्हें उसने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इन संगठनों के सदस्यों को अमेरिका 'अवैध लड़ाके' मानकर कार्रवाई करेगा। हालांकि, ज्ञापन में कार्टेलों के नाम नहीं बताए गए थे और न ही उन मानकों का खुलासा किया गया था जिनका उपयोग अमेरिकी सरकार यह तय करने के लिए करेगी कि कोई व्यक्ति किसी कार्टेल से इतना जुड़ा है कि उसे निशाना बनाया जा सके।

उधर, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह ड्रग्स कार्टेलों का बहाना बनाकर वेनेजुएला की सरकार बदलने और लैटिन अमेरिका में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ने की कोशिश कर रहा है।

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

बिहान योजना से संवारी मीना ने अपना जीवन, लखपति दीदी बन अर्जित कर रही एक लाख रुपये से भी अधिक आय

रायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर शुरू की गई लखपति दीदी पहल ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक सशक्त माध्यम बनाने प्रयास की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को आजीविका की गतिविधियों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय को अधिक से अधिक बढ़ाने के उद्देश्य ने कई महिलाओं की जिंदगी बदली रही है, उन्ही में से एक हैं बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के विकासखंड राजपुर के ग्राम अमडीपारा की श्रीमती मीना देवी गुप्ता।

महिला स्व-सहायता समूह ने बदली जीवन

श्रीमती मीना बिहान से जुड़कर अन्य ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी है। मीना, आरती स्व-सहायता समूह से जुड़ी हैं और आजीविका के छोटी-छोटी गतिविधियां कर आज अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रही है। वे बताती हैं कि उनके पति कृषि कार्य करते हैं। प्राप्त आमदनी से परिवार की जरूरतों और बच्चों की पढ़ाई के खर्च पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इन कठिन परिस्थिति से उबरने के लिए मीना ने महिला स्व-सहायता समूह का सहारा ली और अपने जीवन को बदलने की ठानी। श्रीमती मीना गुजरे दिनों को याद करते हुए बताती हैं कि परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए महीनों लग जाते थे पैसे इक्ठे करने में। तब जाकर छोटी-छोटी जरूरते पूरी होती थी।

समूह से जुड़ने के बाद मीना ने सीआईएफ की राशि का उपयोग कर विभिन्न आजीविका गतिविधियों की शुरुआत की। उन्होंने मिल, किराना दुकान संचालन का कार्य प्रारंभ किया। मीना अपनी मेहनत और लगन से अलग-अलग स्रोतों से एक लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय अर्जित कर रही है। मीना को कृषि कार्य से 70 हजार, किराना दुकान से 40 हजार और एफएलसीआरपी से 50 हजार रुपए तक की आमदनी प्राप्त हो रही है। आज इन सभी आय स्रोतों से उनकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो गई है। अब उनके परिवार में खुशहाली आ गई है और परिवार का जीवन स्तर पहले से अधिक बेहतर हो गया है।

बिहान योजना से महिलाएं बनी आत्मनिर्भर

मीना देवी की सफलता साबित करती है कि जब महिलाओं को शासन की नीतियों और पहल से अवसर और संसाधन मिलते हैं, तो वे अपने जीवन को आत्मनिर्भरता और सफलता की ओर ले जा सकती हैं। मीना कहती हैं कि बिहान योजना ने मुझे और मेरे जैसी कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। अब मैं अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हूं। उन्होंने महिलाओं के जीवन को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में किये गये पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त किया।

कोतवाली पुलिस राजनांदगांव की कार्यवाही, एक आरोपी को धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार

आरोपी के कब्जे से 49 पौवा देशी प्लेन मदिरा मात्रा 8.820 बल्क लीटर कीमती 3920 रूपये एवं एक्टीवा मोटर सायकल किमती 20,000 रूपये किया गया जप्त

राजनांदगांव । पुलिस अधीक्षक महोदय राजनादगांव मोहित गर्ग (भा0पु0से0) के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन (भा0पु0से0) राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक नंदकिशोर गौतम के नेतृत्व मे थाना कोतवाली पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों एवं अवैध शराब बिक्री करने वालो के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 14.10.2025 को मुखबीर की सूचना पर घेराबंदी कर घटना स्थल गंज चौक सोनकर कृषि केन्द्र के सामने राजनांदगांव में आरोपी विनित लोन्हारे पिता स्व0 भंवर लाल लोनहारे उम्र 21 वर्ष साकिन राम नगर पॉवर हाउस के पास राजनांदगांव थाना सिटी कोतवाली जिला राजनांदगाव (छ0ग0) को अवैध रूप से बिक्री करने शराब को एक्टीवा मोटर सायकल क्रमांक सी0जी0 08 ए0एम0-5966 से परिवहन कर ले जाते रंगे हाथ पकड़ा गया जिसके कब्जे से 49 पौवा देशी प्लेन शराब 8.820 बल्क लीटर किमती 3,920 रूपये एवं उक्त एक्टीवा वाहन को जप्त कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलॉफ प्रर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने से अप0क्र0 617/25 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

जशपुर जिले में खारूंग नदी पर भेलवा एनीकट योजना को मिली प्रशासकीय स्वीकृति

125 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई व पेयजल सुविधा होगी उपलब्ध

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा जशपुर जिले के विकासखंड फरसाबहार की खारूंग नदी पर भेलवा एनीकट योजना कार्य हेतु 5 करोड़ 40 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह स्वीकृति राज्य शासन द्वारा जारी की गई है।

इस योजना के क्रियान्वयन से ग्रामवासियों को निस्तारी, पेयजल, भू-जल संवर्धन तथा कृषकों द्वारा स्वयं के साधनों से लगभग 125 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्र में जल उपलब्धता बढ़ाने, भू-जल पुनर्भरण को प्रोत्साहित करने और स्थानीय कृषि उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से तैयार की गई है।

निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरांत ही निविदा आमंत्रित की जाएगी। योजना की ड्रॉइंग एवं डिज़ाइन का अनुमोदन सक्षम अधिकारी से सुनिश्चित किया जाएगा। प्रस्तावित निर्माण कार्य की निविदा तभी की जाएगी जब कम से कम 75 प्रतिशत बाधा रहित भूमि उपलब्ध हो। कार्य की निविदा प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक रूप से संपन्न की जाएगी। भू-अर्जन की आवश्यकता होने पर व्यय स्वीकृत राशि की सीमा के भीतर किया जाएगा तथा किसी अन्य मद से राशि का स्थानांतरण बिना पूर्व स्वीकृति के नहीं किया जाएगा। यदि भू-अर्जन की आवश्यकता नहीं है, तो निर्माण कार्य केवल शासकीय भूमि पर ही कराया जाएगा। निर्माण कार्य के दौरान प्रयुक्त सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी और किसी भी स्तर पर गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारण कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।कार्य को स्वीकृत लागत एवं निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। समय-सीमा में अनावश्यक वृद्धि नहीं की जाएगी, और आवश्यकता पड़ने पर ही सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार समय में बढ़ोतरी प्रदान किया जा सकेगा। निर्माण कार्य की निविदा दर या प्रस्तावित मात्रा में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है, तो पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग, अंबिकापुर को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि कार्य के सभी तकनीकी एवं वित्तीय पहलुओं का पालन छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार किया जाए तथा योजना की लोकहित, गुणवत्ता और मितव्ययिता पर विशेष ध्यान दिया जाए। भलवा एनीकट योजना के माध्यम से फरसाबहार क्षेत्र के ग्रामीणों को पेयजल, सिंचाई और जल संरक्षण की दीर्घकालिक सुविधा प्राप्त होगी। यह योजना राज्य शासन की ग्रामीण विकास, जल संवर्धन एवं कृषि सशक्तिकरण के प्रति स्थायी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

रायपुर के डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड में होगी प्री-टेस्ट जनगणना, तैयारी शुरू

रायपुर। नगर निगम रायपुर के जोन क्रमांक 10 के अंतर्गत आने वाला डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड (वार्ड क्रमांक 52) छत्तीसगढ़ में नगरीय क्षेत्र के प्री-टेस्ट जनगणना कार्य के लिए चयनित किया गया है। यह चयन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के जनगणना निदेशालय के दिशा-निर्देशों के तहत किया गया है। प्री-टेस्ट जनगणना से पहले, वार्ड क्षेत्र में लगभग 8000 भवनों की पहचान कर उन्हें क्रमांकित करने एवं सूचीबद्ध करने का कार्य नगर निगम की टीम द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। यह कार्य जोन 10 के राजस्व और नगर निवेश विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के निर्देशानुसार, जोन कमिश्नर विवेकानंद दुबे के नेतृत्व में तथा सहायक अभियंता योगेश यदु (नोडल अधिकारी) और जोन सहायक राजस्व अधिकारी गौरीशंकर साहू (सहायक नोडल अधिकारी) की निगरानी में यह अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम ने स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वे भवन क्रमांकन एवं सूचीकरण के इस कार्य में नगर निगम की टीम को पूरा सहयोग प्रदान करें, जिससे जनगणना की तैयारियों को सुचारु रूप से संपन्न किया जा सके। इस संबंध में भारत सरकार के जनगणना निदेशालय द्वारा 17 अक्टूबर 2025 को एक अहम बैठक आयोजित की गई है, जिसमें प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में होने वाले जनगणना पूर्व परीक्षण की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी।

सरगुजा के लाल माटी क्षेत्र में हाथियों का आतंक, युवक की कुचलकर मौत

सरगुजा। जिले के लुंडरा वन परिक्षेत्र के ग्राम लाल माटी में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार रात हाथियों के झुंड ने ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल के पास एक युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना के बाद से इलाके में भय और दहशत का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, हादसे के वक्त क्षेत्र में करीब 25 हाथियों का दल मौजूद था। मृतक की पहचान राजकुमार नाइक (19 वर्ष), पिता चंदू नाइक, निवासी भोपाल के रूप में हुई है। हाथियों का यह झुंड नेशनल हाईवे 43 के आसपास भी देखा गया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अंबिकापुर के रेंजर निखिल पैकरा और लुंडरा रेंज के अधिकारी निगरानी कर रहे हैं और ग्रामीणों से हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। साथ ही, हाथियों को आबादी से दूर खदेड़ने की कोशिशें जारी हैं। वन विभाग ने पीड़ित परिवार को तात्कालिक सहायता के रूप में ?25,000 की आर्थिक मदद प्रदान की है। वहीं, पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार गश्त कर रही है।

किसान हित सर्वोपरि धान खरीदी में कोई पात्र कृषक न छूटे : कलेक्टर, धान खरीदी केन्द्रों में सभी तैयारियां सुनिश्चित

कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में धमतरी जिले की सराहना, कलेक्टर ने टीम को दी बधाई

धमतरी । कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने आज साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक लेकर आगामी 15 नवम्बर से प्रारंभ होने वाली समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक धान खरीदी केन्द्र में स्वच्छता, पेयजल, छायादार व्यवस्था, बारदाना, तोलक कांटा, परिवहन व्यवस्था तथा कंट्रोल रूम की स्थापना समय पर सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र किसान धान विक्रय से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर मिश्रा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिचौलियों,कोचिया और अवैध धान परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जाए और आवश्यकता अनुसार त्वरित कार्रवाई की जाए। बैठक में अपर कलेक्टर रीता यादव, सभी एसडीएम एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर मिश्रा ने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में धमतरी जिले की कार्यप्रणाली की सराहना की गई। जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति कल्याण, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, प्रधानमंत्री जनमन, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा प्रधानमंत्री सूर्यघर जैसी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की प्रशंसा मुख्यमंत्री द्वारा की गई। इस उपलब्धि पर कलेक्टर ने समस्त जिला अधिकारियों एवं टीम को बधाई दी और कहा कि शासन एवं प्रशासन की मंशा के अनुरूप जनहित में इसी प्रकार बेहतर कार्य करते रहें। उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देशों की जानकारी साझा करते हुए कहा कि सभी अधिकारी-कर्मचारी कार्यालयीन समय का पालन करें। लोक निर्माण विभाग को उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों, पुल-पुलियों की मरम्मत शीघ्र पूर्ण करने तथा शहर के प्रमुख चौक-चौराहों जैसे कोलियारी चौक, भखारा चौक, कुकरेल और सिहावा चौक की सड़कों के सुधार कार्य तत्काल आरंभ करने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सड़क किनारे अव्यवस्थित रूप से खड़े वाहनों एवं ढाबों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि मलेरिया या अन्य संक्रामक रोग का कोई भी मामला सामने आने पर तत्काल मरीज को जिला अस्पताल लाकर उचित उपचार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचे। कलेक्टर मिश्रा ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को उत्कृष्ट पहल बताते हुए अधिकारियों से कहा कि इस योजना का अधिकतम लाभ जनता तक पहुंचाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार एवं शिविरों का आयोजन किया जाए।

रजत जयंती महोत्सव पर

विशेष-धमतरी जिले में सौर सुजला योजना

धमतरी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2016-17 में प्रारंभ की गई सौर सुजला योजना आज राज्य के किसानों के जीवन में खुशहाली का नया अध्याय लिख रही है। विशेषकर धमतरी जिले में यह योजना किसानों के लिए संजीवनी साबित हुई है। जहां पहले किसान केवल वर्षा आधारित खेती पर निर्भर रहते थे और सिंचाई की कमी से उत्पादन प्रभावित होता था, वहीं अब सूर्य की ऊर्जा से संचालित सोलर पंप किसानों के लिए बारहमासी खेती का भरोसेमंद साधन बन गए हैं।

धमतरी जिले में अब तक कुल 3068 सोलर पंपों की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (क्रेडा) द्वारा की जा चुकी है। इन पंपों से किसानों को धान, गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन, सब्ज़ी और फल-फूल जैसी फसलों का उत्पादन बड़े पैमाने पर करने का अवसर मिला है।गांव-गांव में किसान अब एक सीजन की जगह पूरे साल खेती कर पा रहे हैं, जिससे उनकी आय दोगुनी हुई है और जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव आया है।

ग्राम गोरेगांव के किसान अमृत लाल बताते हैं कि पहले बरसात पर ही खेती करना पड़ता था। बिजली की लाइन खेत तक नहीं पहुंची थी। अब सौर पंप लगने से साल भर सब्ज़ी और धान की खेती कर पा रहा हूँ। आमदनी भी बढ़ गई है और बच्चों की पढ़ाई-लिखाई अच्छे से कर पा रहा हूँ।डीजल पंप से खेती करना बहुत महंगा पड़ता था। तेल के दाम भी बढ़ते रहते थे। अब सूरज की रोशनी से खेतों को पानी मिलता है, कोई खर्च नहीं होता। यह योजना हम जैसे छोटे किसानों के लिए वरदान है।

ग्राम भोथली के युवा किसान रामेश्वर ने उत्साहित होकर कहा ङ्क पहले गांव में खेती छोड़कर बाहर नौकरी ढूँढने जाना पड़ता था। अब सोलर पंप से अच्छी खेती-बाड़ी हो रही है ।कई महिला किसान सब्ज़ी की खेती कर शहर में बेच रही है । महीने में इतना कमा लेती है कि बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं रही।इस योजना के अंतर्गत किसानों को 90 प्रतिशत तक अनुदान शासन द्वारा दिया जाता है। केवल शेष राशि उन्हें अंशदान के रूप में देनी होती है। इतना ही नहीं, एनिकट, स्टॉप डेम एवं चेक डेम के किनारों पर 3 से 5 एचपी क्षमता वाले सरफेस सोलर पंप 97 प्रतिशत अनुदान पर लगाए जा रहे हैं। इससे जल स्रोत के पास बसे छोटे और सीमांत किसान अत्यधिक लाभान्वित हो रहे हैं।

लक्ष्य और उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष 2024-25 में सौर सुजला योजना के सातवें चरण में धमतरी जिले को 400 सोलर पंपों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। इसके विरुद्ध अब तक 252 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी स्वीकृति और स्थापना प्रक्रिया क्रेडा द्वारा की जा रही है। वहीं वर्ष 2025-26 के फेस-09 अंतर्गत जिले को 205 सोलर पंप का लक्ष्य मिला है, जिनमें से 165 पंप स्थापित किए जा चुके हैं और शेष पर तेजी से कार्य चल रहा है।

आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन इस योजना ने जिले की कृषि व्यवस्था को एक नई दिशा दी है। किसान अब खरीफ और रबी दोनों मौसम में खेती कर रहे हैं। उत्पादन बढ़ने से उनकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अतिरिक्त पैदावार से न केवल किसानों की आय दोगुनी हुई है, बल्कि गांवों में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं।खेतों में मजदूरों, परिवहन और कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियों में रोजगार मिलने से बेरोजगारी की समस्या भी घट रही है।

धर्मांतरण पर सरकार बेहद सख्त, चंगाई सभा पर लगे रोक, नहीं तो होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने कहा- एसपी के जूतों की धमक होनी चाहिए

रायपुर ।

कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन सीएम विष्णुदेव साय के कड़े तेवर दिखे. चंगाई सभा को लेकर सीएम साय ने कड़ी नाराजगी जताई और चंगाई सभा पर रोक लगाने के सख्त निर्देश दिए. साथ ही धर्मांतरण पर पूर्ण रोक लगाने की बात कही। सीएम ने कोरबा, राजनांदगांव, धमतरी, महासमुंद एसपी के काम पर नाराजगी जताते हुए जमकर फटकार लगाई. उन्होंने कहा, एसपी के जूतों की धमक शहर तक आनी चाहिए. कलेक्टर-एसपी के बीच तालमेल नहीं होने से बलौदबजार जैसी घटनाएं होती है. छोटे अपराध पर लगाम नहीं लगते और वही बड़े रूप लेते हैं. गृहमंत्री विजय शर्मा ने महासमुंद एसपी को चालान समय पर पेश नहीं होने को लेकर कड़ी फटकार लगाई. गृहमंत्री ने कहा, महासमुंद छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं है. सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि पुलिस की छवि ऐसी होनी चाहिए, जिससे अपराधियों में कानून का भय और आम नागरिकों में सुरक्षा का अहसास उत्पन्न हो. सीएम साय आज मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे. कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस में प्रदेश की कानून-व्यवस्था की समग्र स्थिति, मादक पदार्थ नियंत्रण, सड़क सुरक्षा, साइबर अपराधों की रोकथाम और प्रशासनिक समन्वय को सुदृढ़ करने जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई. इस अवसर पर गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव विकास शील, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. सीएम साय ने कहा कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक दोनों की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण है. जिन जिलों में दोनों के बीच समन्वय मजबूत है, वहां बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि कानून-व्यवस्था के मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई को प्रशासनिक उदासीनता माना जाएगा और ऐसे मामलों में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी. सीएम ने निर्देश दिए कि सड़कों पर अव्यवस्था फैलाने, चाकूबाजी और हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए. गौ-तस्करी और धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मामलों पर सघन निगरानी रखी जाए और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि जिन जिलों ने अपराध नियंत्रण में उल्लेखनीय सुधार किया है, उनके अनुभवों को अन्य जिलों में मॉडल के रूप में लागू किया जाए. सीएम साय ने नशाखोरी और मादक पदार्थों की अवैध तस्करी पर सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि नशा अपराधों की जड़ है, और इसे समाप्त करना ही कानून-व्यवस्था सुधार की पहली शर्त है.

सीएम साय ने एनकॉर्ड के तहत राज्यव्यापी अभियान चलाने, सीमावर्ती जिलों में तस्करी पर रोक लगाने और एनडीपीएस एक्ट के तहत समय-सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराने के लिए जनजागरूकता अभियान चलाया जाए सीएम ने कहा कि प्रदेश में घुसपैठियों की पहचान और नियंत्रण के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित की गई है. उन्होंने निर्देश दिए कि सीमावर्ती जिलों में सघन जांच की जाए और संदिग्ध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो।

CHHATTISGARH STATE POWER GENERATION CO. LTD.
(A Govt. of Chhattisgarh Undertaking) CIN: U40108CT2003SGC015821

No.15-06/S&P/EE-III/C&I/E&T/P/TN-155/25/3065 Marwa, dtd. 19-10-2025

NOTICE INVITING E-TENDER NO TN-155/2025: -

Online bids are invited by the undersigned through CSPCL e-bidding system (SAP SRM) from firms/suppliers for procurement of materials mentioned below for 2x500MW, ABVTPS, CSPGCL, Janjgir-Champa: -

S. No.	Tender Specification No.	RFx No. (E -Tender No.)	Particulars	Last Date/Time of submission of bid.	Tender Fee	EMD
01.	15-06/ S&P/ EE-III/ E&T/P/ T-245/25	8100046642	Supply of instrument cable for 6 nos Medium Voltage VFD Drives in BHEL Make 900KW, 6.6 kV CEP Motors installed at U#1 and U#2 of ABVTPS, CSPGCL, Janjgir -Champa.	13.11.2025 15:30 Hrs	Rs.590/- (Rs.500/- + GST @ 18%)	Rs. 6630/-
02.	15-06/ S&P/ EE-III/ C&I/P/ T-246/25	8100046646	Supply of hydraulic mid-back revolving chair for EWS room at MCR of ABVTPS, CSPGCL, Janjgir-Champa.	14.11.2025 15:30 Hrs	Rs.590/- (Rs.500/- + GST @ 18%)	Rs. 6330/-

The bidder shall deposit the requisite Tender Fee & EMD amount online through our e-bidding portal before due date and time. For other details, please visit our website www.cspc.co.in/CSPGCL/Ebidding/Ebidding web portal. Any Extension/ Corrigendum / amendments, if required, shall be displayed on above websites only.

Superintending Engineer (Procurement)
// SAVE ELECTRICITY FOR THE BENEFIT OF SELF & NATION // O/o The Addl. Chief Engineer (S&P) ABVTPS, CSPGCL, Janjgir-Champa

samvad-45611/1

साईंस कॉलेज छात्रावास में घूसकर बलवा करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। राजधानी के थाना सरस्वती नगर क्षेत्रांतर्गत स्थित साईंस कॉलेज छात्रावास में घूसकर छात्रों के साथ हाथ-मुक्का एवं डंडा से मारपीट करने वाले 6 आरोपियो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है वहीं मारपीट में शामिल अन्य आरोपी फरार है जिनकी पतासाजी की जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसर प्रार्थी उमादास मुखर्जी ने थाना सरस्वती नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह साईंस कॉलेज हॉस्टल में रहकर साईंस कॉलेज में बीएससी अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहा है। दिनांक 12.01.2025 को रात्रि करीबन 11.45 बजे छात्रावास में 50-60 व्यक्तियों का एक गैंग छात्रावास के अंदर प्रवेश कर प्रार्थी सहित अन्य छात्रावासियों के साथ हाथ-मुक्का, डंडा, चाकू से मारपीट करने लगे तथा छात्रों

का सामान चोरी कर फरार हो गये थे। जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना सरस्वती नगर में धारा 115(2), 191(2), 191(3), 333, 304(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। घटना को पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर अमरेश मिश्रा तथा उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम दौलत राम पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक ईशु अग्रवाल,उप पुलिस अधीक्षक क्राईम संजय सिंह, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी सरस्वती नगर को अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना सरस्वती नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना के संबंध में प्रार्थी तथा अन्य छात्रों से विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल तथा उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन कर आरोपियों को चिन्हांकित करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान टीम के सदस्यों को घटना में संलिप्त आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। जिसपर टीम के सदस्यों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रकरण में आरोपी मोनेश उर्फ मोन्टू केसरकर पिता शिवहरि केसरकर उम्र 28 साल निवासी फूलचौक प्रकाश फटाका दुकान के सामने थाना गोलबाजार रायपुर, धर्माशुं सोनपिपरे पिता विनोद सोनपिपरे उम्र 24 साल निवासी फूलचौक नयापारा फटाका एण्ड फटाका दुकान के पास थाना गोलबाजार रायपुर, गेबिन यादव पिता ओम यादव उम्र 25 साल निवासी शारदा चौक बंजारी रोड थाना गोलबाजार रायपुर, प्रतीक यादव पिता अश्वन यादव उम्र 25 साल निवासी शारदा चौक थाना गोलबाजार रायपुर, आकाश गुप्ता उर्फबाबू पिता संजय गुप्ता उम्र 19 साल निवासी महंत तालाब कोटा शिव मंदिर के पास थाना सरस्वती नगर रायपुर तथा थानेश्वर उर्फसोनू साहू पिता धनसाय साहू उम्र 31 साल निवासी कुशालपुर मिट्टी खदान के पास देवांगन किराना दुकान के पीछे थाना पुरानी बस्ती रायपुर को पतासाजी कर पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों द्वारा अपने साथ अन्य 25-30 व्यक्तियों के साथ मिलकर उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है।

महापौर मीनल चौबे जापान में कर रही है रायपुर नगर पालिक निगम का प्रतिनिधित्व

जापान में 14 से 16 अक्टूबर तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मेयर फोरम में हुई शामिल

रायपुर । नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे जापान के टोयोटा सिटी में दिनांक 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2025 तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मेयर फोरम 2025 में रायपुर नगर पालिक निगम का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। यह तीन दिवसीय वैश्विक मंच विश्व के नगरों और संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के बीच सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीय क्रियान्वयन और नवाचारपूर्ण शहरी विकास पर केंद्रित है।

फोरम के प्रथम दिवस पर विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों ने अपने-अपने नगरों की चुनौतियों और उनके समाधान पर विचार साझा किए। चर्चाओं में प्लास्टिक रीसाइक्लिंग को बढ़ावा, स्कूलों में कचरे का पृथक्करण तथा रिड्यूस,रियूज,रिसायकल (आरआरआर) की जागरूकता को शैक्षणिक स्तर पर शामिल करने जैसे विषय प्रमुख रहे।

प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि अपशिष्ट से उपयोगी उत्पाद बनाकर पर्यावरण संरक्षण व स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

जापान द्वारा प्रस्तुत लो कॉर्बन सिटी मास्टरप्लान के तहत क्लीनर ड्रेन्स लेस फुड्स और साउंड मेटेरियल्स सायकल सोसायटी की अवधारणा साझा की गई, जिसका उद्देश्य कम-कार्बन, स्वच्छ और जलवायु-लचीले शहरों का निर्माण है।

फोरम में विश्व बैंक, अन-हेबिटेट, यूएनईपी,यूएनआईडीओ सहित जापान, कोरिया, मलेशिया, रवांडा, पाकिस्तान और ग्रीस के प्रतिनिधि शामिल हुए।

मंगोलिया के उलानबटार सिटी ने हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट, जबकि मलेशिया के पेनांग सिटी काउंसिल ने सुरक्षित एवं लचीले आवास विषय पर प्रस्तुति दी।

युगांडा के मसाका सिटी के मेयर ने भी अनियोजित बस्तियाँ, अवसंरचना की कमी और जलवायु चुनौतियों पर अपने अनुभव साझा किए।

केडीवी मिशन ने स्कूली छात्रों को कराया सामूहिक भोज

कवर्धा। जिला कबीरधाम के तत्वावधान में शासकीय दृष्टि एवं मुक्बधिर स्कूल ग्राम सिघनपुरी जिला कबीरधाम में इस साल के पावन दिपावली के शुभअवसर पर जीव दया और आतम पूजा के माध्यम से सभी बच्चों को भोजन खिलाकर के डी वी मिशन के प्रतिनिधि एवं आमिन माता महिला मंडल के द्वारा सेवा कार्य किया गया।

जिसमें के डी वी मिशन के राज्य उप महिला प्रतिनिधि मति खिलेश्वरी साहू एवं के डी वी मिशन जिला कबीरधाम के जिला प्रतिनिधि रोशन साहू , जिला उप प्रतिनिधि दानीदास मानि. जिला युवा प्रतिनिधि ब्रम्हा पटेल, जिला महिला प्रतिनिधि मति लक्ष्मीन साहू, जिला परोपकारी प्रतिनिधि गोवर्धन साहू जी जिला सलाहकार महंत अमृतदास साहेब जी, जिला सलाहकार कबीरधाम जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू महंत तुलसी साहेब जी, सुदर्शन साहू ,शीशुपाल, नरेन्द्र मानिकपुरी, जलेश्वर साहू ,कालीदास,उमराज पटेल,टुम्मन साहू , जगेलाल,चुरावन साहू, दिलीप साहब बाड़ा,जिसमें सभी की उपस्थिति में सेवा कार्य सम्पन्न हुआ।

तेलीबाँधा से टाटीबंध तक मार्ग विभाजक क्षेत्र में फ्लैक्स लगाना प्रतिबंधित

रायपुर । महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम नगर निवेश विभाग ने तेलीबाँधा से टाटीबंध तक मार्ग विभाजक क्षेत्र में नो फ्लैक्स जोन स्टीकर लगाकर विज्ञापन बोर्ड लगाना प्रतिबंधित किया गया है।

रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर मीनल चौबे, नगरीय नियोजन और भवन अनुज्ञा विभाग के अध्यक्ष मनोज वर्मा और आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर रायपुर नगर पालिक निगम के नगर निवेश विभाग द्वारा राजधानी शहर रायपुर के जीईमार्ग में स्थित तेलीबाँधा चौक से लेकर टाटीबंध चौक तक के मध्य मार्गविभाजक क्षेत्र में नो फ्लैक्स जोन स्टीकर लगवाया गया है. नगर निवेश विभाग द्वारा मार्गविभाजक क्षेत्र तेलीबाँधा चौक से लेकर टाटीबंध चौक तक के मध्य विज्ञापन बोर्ड लगाना प्रतिबंधित कर दिया गया है।

राजधानी के डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड का प्रदेश में जनगणना के लिए नगरीय क्षेत्र में प्री टेस्ट जनगणना पूर्व परीक्षण के लिए

रायपुर। भारत सरकार गृह मंत्रालय जनगणना कार्य निदेशालय के आदेशानुसार रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 10 के डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 52 का छत्तीसगढ़ राज्य में जनगणना के लिए नगरीय क्षेत्र में प्री टेस्ट जनगणना पूर्व परीक्षण के लिय चयन हुआ है।

भारत सरकार गृह मंत्रालय जनगणना कार्य निदेशालय के आदेशानुसार रायपुर नगर पालिक निगम के जोन क्रमांक 10 के अंतर्गत डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड क्रमांक 52 को छत्तीसगढ़ राज्य में जनगणना के लिए नगरीय क्षेत्र में प्री टेस्ट जनगणना पूर्व परीक्षण हेतु चयनित किया गया है। रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम जोन 10 जोन कमिश्नर विवेकानंद दुबे के नेतृत्व एवं नोडल अधिकारी सहायक अभियंता योगेश यदु, सहायक नोडल अधिकारी जोन सहायक

राजस्व अधिकारी गौरीशंकर साहू की उपस्थिति में नगर निगम जोन 10 राजस्व विभाग और नगर निवेश विभाग की टीम के कर्मचारियों द्वारा वार्ड क्रमांक 52 क्षेत्र अंतर्गत स्थित सभी लगभग 8000 जनगणना भवनों में भवन संख्या डालने और भवनों को सूचीबध्द करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

रायपुर नगर पालिक निगम ने नगर पालिक निगम जोन 10 के डॉ राजेन्द्र प्रसाद वार्ड क्रमांक 52 क्षेत्र की समस्त रहवासी जनता से प्री टेस्ट जनगणना पूर्व परीक्षण के कार्य में नगर पालिक निगम रायपुर जोन कमांक 10 के राजस्व विभाग और नगर निवेश विभाग की टीम को सभी लगभग 8000 जनगणना भवनो मे भवन सख्या डालने और भवनों को सूचीबध्द करने के कार्य में भारत सरकार गृह मंत्रालय जनगणना कार्य निदेशालय के आदेशानुसार किये जा रहे आवश्यक कार्य में सहयोग देने की विनम्र अपील की है।

भारत सरकार गृह मंत्रालय जनगणना कार्य निदेशालय के आदेशानुसार जनगणना निदेशक द्वारा प्रदेश में जनगणना के लिए नगरीय क्षेत्र में प्री टेस्ट जनगणना पूर्व परीक्षण हेतु 17 अक्टूबर 2025 को जनगणना निदेशालय में आवश्यक बैठक बुलाई है।

मोटरसाइकिल चोरी करने वाले ग्राम लटुवा निवासी 04 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

राजनांदगांव। प्रार्थी धर्मेंद्र रजक निवासी ग्राम अर्जुनी थाना भाटापारा ग्रामीण द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 25.08.2025 को रात्रि 9:00 बजे ग्राम शुक्लाभाटा से वापस अपने घर अर्जुनी अपनी मोटरसाइकिल छत्त22 ङ्क2557 में निकला था, कि शुक्लाभाटा मोड लटुवा रोड में प्रेश्र होने के लिए गाड़ी में चाबी को छोड़कर मैदान तरफ चला गया था, वापस आकर देखा तो वहां पर मोटरसाइकिल नहीं था, जिसे कोई अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया था। कि रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्र. 845/2025 धारा 303(2),3(5) बीएनएस का प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा जांच एवं विवेचना कार्यवाही किया गया।

नशे के अवैध कारोबार पर कड़ी कार्रवाई : तीन माह के लिए आरोपी पुनीत खरे को जेल भेजा गया

संभागायुक्त महादेव कावरे के निर्देश पर की गई कार्रवाई

रायपुर । संभागायुक्त महादेव कावरे के निर्देश पर मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर पुनीत खरे निवासी ग्राम छपोरा वार्ड नंबर 11, थाना विधानसभा, जिला रायपुर (छ.ग.) के विरुद्ध (एनडीपीएस) एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी विधानसभा, शिवेन्द्र राजपूत द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया कि आरोपी पुनीत खरे के विरुद्ध थाना विधानसभा में एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन प्रकरण पंजीबद्ध हैं। आरोपी आदतन आपराधिक

प्रवृत्ति का है तथा अवैध गांजा बिक्री के व्यवसाय में संलिप्त है। उसके आपराधिक कृत्यों से आसपास के लोगों में आक्रोश व्याप्त है, साथ ही नशे के अवैध कारोबार से जनता के स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अनावेदक को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। तथ्यों, साक्ष्यों एवं प्रस्तुत शपथ कथनों पर विचारोपरांत यह पाया गया कि आरोपी के विरुद्ध पिट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। उक्त तथ्यों के आधार पर स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ (अवैध व्यापार निवारण) अधिनियम 1988 की धारा 11 के अंतर्गत संभागायुक्त श्री कावरे ने पुनीत खरे को तीन माह के लिए केंद्रीय जेल भेजने का आदेश दिया। संभागायुक्त महादेव कावरे के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई से अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त प्रशासनिक रुख का स्पष्ट संदेश गया है। प्रशासन द्वारा ऐसे तत्वों पर आगे भी इसी प्रकार कठोर कदम उठाए जाएंगे।

कन्नौजिया क्षत्रिय समाज रायपुर उप समिति ने सर्वसम्मति से निर्वाचन, संपन्न, किशोर सिंह बने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बृज ठाकुर को बनाया

मोतीबाग प्रेस क्लब में समाज के वरिष्ठजनों की उपस्थिति कार्यक्रम संपन्न हुआ

दैनिक लोकशक्ति,रायपुर। कन्नौजिया क्षत्रिय समाज रायपुर की उप समिति का सर्वसम्मति से चुनाव सम्पन्न हुआ। जिसमें सामाजिक बैठक का आयोजन मोतीबाग प्रेस क्लब में रविवार 12 अक्टूबर 2025 को किया गया। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि रामबिहारी सिंह परिहार, नवलकिशोर सिंह रहे। रायपुर उपसमिति के मार्गदशक मनौज सिंह बघेल और केंद्रीय पर्यवेक्षक गजानंद सिंह परिहार की मौजूदगी में रायपुर उपसमिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सहित चुने गए जिसमें जिसमें अध्यक्ष किशोर सिंह, उपाध्यक्ष ब्रिज ठाकुर उर्फ गगन,कनिष्ठ उपाध्यक्ष - सूरज सिंह परिहार, कोषाध्यक्ष - पुष्पेंद्र सिंह परिहार, महिला उपाध्यक्ष -रंजना सिंह सोलंकी (पति श्री - श्रीनिवास सिंह सोलंकी), सचिव -प्रदुमन सिंह भुवाल, महिला सचिव नेहा सिंह (पति श्री प्रकाश सिंह) सह सचिव - आयुष सिंह गहरवार, शहर प्रमुख - अधीर सिंह भुवाल और रामधन सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। वही उपसमिति के

कार्यकारणी सदस्यों में बतौर अविभाष सिंह दीक्षित ,रामेश्वर सिंह श्रीनेत, अजयपाल सिंह सोलंकी , राकेश सिंह बैस ,भूपेंद्र सिंह भुवाल , मनुराज सिंह भुवाल, ब्रजपाल सिंह भुवाल, रामभद्र सिंह बैस, दिलीप सिँह परिहार ,प्रकाश सिंह परिहार, हर्ष सिंह बैस,श्रीनिवास सिंह बैस को बनाया गया।

रायपुर उप समिति के गठन की शुभकामनाएं देते हुए उप समिति के मार्गदर्शक मनोज सिंह बघेल ने कहा कि समाज के विकास के लिए एकता बहुत जरूरी है। उन्होंने अभी हाल ही हुई दुर्घटना पर जोर देते हुए कहा कि गुरुवाईन डबरी वाले मामले में समाज के सभी लोगों के आगे आने से मृतक के परिजन को आर्थिक मुआवजा मिलने से काफी संभल मिला। निश्चित ही इसके लिए हमारी एकता और सभी जनो की सहयोग से ही धरना-प्रदर्शन कामयाब रहा। मैं आगे भी रायपुर उपसमिति के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों से अपेक्षा करता हूं कि समाज के विकास के लिए प्रति हमारी प्रतिबद्धता, सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाहन निःस्वार्थ भाव करते रहेंगे।

इस अवसर रायपुर उपसमिति के नव निर्वाचित सदस्यों ने एक सुर में कहा है कि समाज के विकास हम सभी का सहयोग सकारात्मक होगी, रायपुर में कन्नौजिया क्षत्रिय समाज के लिए सामाजिक भवन के लिए सरकार से जमीन आवंटित कराना हमारी समिति का मुख्य एजेंडा रहेगा। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। समाज के हित में हम कार्य करने के लिए हम सब प्रतिबद्धता है।

कार्यक्रम में विशेष रूप से यज्ञ सिंह ठाकुर,सौरभ सिंह परिहार,अनुराग सिंह, कान्हाराज सिंह भुवाल,राणा सिंह, बंशराज सिंह, ऋषिराज सिंह, श्री हरिकपूर सिंह,बल्लभ सिंह राठौर, यश सिंह, योगेश सिंह परिहार, श्रवण सिँह सहित समाज के अन्य लोग मौजूद रहे।

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

संपादकीय

जातिवाद का आखिर समाधान क्या है?

ये कठिन और असहज करने वाले प्रश्न हैं। इनकी तह में जाने पर नजर आएगा कि खुद किस तरह जातिगत पहचान और प्रतिनिधित्व को सामाजिक न्याय का पर्याय बना कर इसके पैरोकारों ने सारा विमर्श जातिवाद पर केंद्रित कर दिया है। इससे वंचित समूहों के बीच व्यापक एकता और समाज के आधुनिकीकरण की संभावनाएं क्षीण हो गई हैं। नतीजतन, जाति के विनाश का वह लक्ष्य पीछे छूट गया है, जिसे केंद्र में रखकर आधुनिक भारत के निर्माण की परियोजना शुरू की गई थी।

इससे कुछ परिवारों और मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों को अवश्य लाभ हुआ है, मगर जातिवाद या जमीनी स्तर पर जातीय भेदभाव को खत्म करने का मार्ग और बाधित ही हुआ है।

नदियों का स्पंदन।

संजीव ठाकुर,

नदिया पहाड़ों से कहती,
तुम जैसे समय हो, मैं जीवन।
तुम ठहरे हो,
इसलिए बह पाती।

अगर तुम भी चलने लगो,
तो मेरी दिशा कौन संभालेगा,
पहाड़ हँसता धीरे-धीरे,
जैसे बूढ़े पिता की हँसी में अपनापन।
तुम्हारा बहना ही मेरा रहना,

तुम हर दिन जाती हो,
पर मेरे भीतर से ही निकलत।
नदिया थोड़ी चुप हुई
उसके पानी में बादल की परछाई
डोलने लगी।

लोग कहते हैं तुम कठोर हो,
वह बोली, पर मैंने देखा है
तुम्हारे भीतर के नमक
को , जो बरसात में बह निकलता ।
पहाड़ ने उत्तर नहीं दिया।

वह जानता शब्दों से ज्यादा गहरी होती
है नदियों की चुप्पी।

थोड़ी देर में हवा बोली
तुम दोनों एक-दूसरे को थामे हुए ,
एक जगह से न हिलना भी

कभी-कभी प्रेम होता है।
नदिया बहती रही
पहाड़ खड़ा रहा
दोनों अपने-अपने रूप में
एक-दूसरे को जीते हुए।

क्योंकि समय और जीवन का यही
रिश्ता है एक बहता , एक ठहरता ,
दोनों मिलकर... सृष्टि का संगीत
रचते ।

QR CODE SCAN
कर प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़िये ऑनलाईन

PM : 2024 - Vishwa Sarkar Ka Vikalp

Modimaya_ Vaidik_Netritva

Rashtriya Ekta

DLF-Vadra-Bhrasht Tantra

Silent Assassins Jan11,1966

Accursed & Jihadi Neighbour

एक लाख एकल शिक्षक स्कूलों की त्रासदी से त्रस्त शिक्षातंत्र

ललित गर्ग
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

भारत में आज भी कई सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चे सिर्फएक शिक्षक के भरोसे सभी विषय पढ़ रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय के साल 2024-25 के आधिकारिक डेटा के मुताबिक देश के कुल 1,04,125 स्कूलों में एक ही शिक्षक सभी कक्षाओं एवं सभी विषयों को पढ़ा रहे हैं। यह आंकड़ा हमारे शिक्षा तंत्र की विफलता को दर्शाता ही नहीं रहा है बल्कि चिन्ताजनक स्थिति को बयां कर रहा है। ये आंकड़े हमारे शैक्षणिक विकास पर एक गंभीर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। ÷शिक्षा किसी राष्ट्र की आत्मा होती है।÷ स्वामी विवेकानंद का यह वाक्य आज भारत की शिक्षा व्यवस्था पर एक कसक बनकर उभरता है। जब शिक्षा की आत्मा घायल होती है तो राष्ट्र का शरीर कभी स्वस्थ नहीं रह सकता।

शिक्षा मंत्रालय के ये हालिया आंकड़े बताते हैं कि एकल शिक्षक स्कूलों में करीब पौने चौंतीस लाख विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। बताया जाता है कि आंध्र प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या सबसे ज्यादा थी, जबकि उसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और लक्षद्वीप का स्थान है। एक तो हमारे देश में शिक्षा का बजट पहले ही बहुत कम है, फिर उस धन का सही उपयोग नहीं हो पाना एक भ्रष्टाचार ही है। इसमें दो राय नहीं कि प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के गिरते स्तर के मूल में हमारे नीति-नियंताओं की अनदेखी ही प्रमुख कारक है। आखिर हम अपने नौनिहालों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं? आखिर उनके बेहतर भविष्य की हम कैसे उम्मीद करें? जाहिर बात है कि एक शिक्षक सामाजिक विषय, भाषा, विज्ञान, अंग्रेजी और गणित में माहिर नहीं हो सकता। एक शिक्षक छात्रों की हाजिरी दर्ज करेगा या पढ़ाई कराएगा? एकल शिक्षक स्कूलों का परिदृश्य भारत के विकास की पौल खोलने वाला है। भले ही एकल शिक्षक स्कूलों में पिछले वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई हो, फिर इतनी बड़ी संख्या में ऐसे स्कूलों का होना हमारी शिक्षा व्यवस्था की बड़ी नाकामी को ही उजागर कर रहा है। यह स्थिति किसी एक आंकड़े की नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य की गहरी त्रासदी की तस्वीर है।

कल्पना कीजिए-एक शिक्षक जो प्रशासनिक काम भी करता है, मिड-डे मील की निगरानी भी करता है और साथ में सभी कक्षाओं को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी निभाता है। क्या वह शिक्षक शिक्षक रह जाता है या व्यवस्था का बोझ उठाने वाला मज़दूर बन जाता है? इन बच्चों की शिक्षा कैसी होगी, जिनके लिए ज्ञान का एकमात्र द्वार ही थकान, उपेक्षा और तंगहाली से भरा है? यह संकट केवल ग्रामीण भारत तक सीमित नहीं है। शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहाँ विषय विशेषज्ञों की कमी, प्रयोगशालाओं की अनुपस्थिति और शिक्षण संसाधनों का अभाव है। नई शिक्षा नीति 2020 समग्र शिक्षा की बात करती है, लेकिन जब आधारभूत ढाँचा ही अपूर्ण हो तो नीतियाँ केवल दस्तावेज़ बनकर रह जाती हैं। हम 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, पर क्या एकल शिक्षक स्कूलों की यह स्थिति उस दिशा में कोई सार्थक कदम का संकेत है?

यह विडंबना है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, पर उसके बचपन की शिक्षा का यह हाल है। शिक्षा पर सरकारी व्यय जीडीपी का केवल 2.9 प्रतिशत है, जबकि विकसित देशों में यह 5 से 6 प्रतिशत तक है। जब शिक्षा ही निवेश नहीं बनेगी, तो विकास का आधार कहाँ से आएगा? समस्या केवल शिक्षक संख्या की नहीं, बल्कि शिक्षकों की भर्ती, प्रशिक्षण और संसाधनों की भी है। राज्यों में नियुक्ति प्रक्रियाएँ वर्षों तक लटकी रहती हैं, स्थानांतरण नीति अव्यवस्थित है, और जो शिक्षक हैं भी, उन्हें आधुनिक शिक्षा पद्धति, डिजिटल शिक्षण, नवाचार और नैतिक मूल्य आधारित शिक्षण के प्रशिक्षण से वंचित रखा गया है। यह स्थिति उस समय और अधिक विडंबनापूर्ण लगती है जब हम हर मंच पर ÷नया भारत÷, ÷विकसित भारत÷ और ÷विश्वगुरु भारत÷ के नारे लगाते हैं। शिक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देखने की आवश्यकता है। रक्षा और स्वास्थ्य की तरह शिक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

शिक्षक भर्ती में पारदर्शिता और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित हो, दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों का समुचित समायोजन किया जाए, तकनीक के माध्यम से डिजिटल शिक्षा का विस्तार हो और शिक्षकों को केवल वेतनभोगी कर्मचारी नहीं बल्कि राष्ट्रनिर्माता के रूप में सम्मान मिले। महात्मा गांधी ने कहा था, ÷यदि हमें भारत को पुनः महान बनाना है, तो शिक्षा को पुनः मानवीय बनाना होगा।÷ आज शिक्षा केवल परीक्षा और नौकरी तक सीमित हो गई है, जबकि उसका उद्देश्य चरित्र निर्माण और विवेक जागरण होना चाहिए। यदि 34 लाख बच्चे एकल शिक्षक के भरोसे हैं, तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक संवेदनहीनता का प्रमाण है। भारत तभी विकसित होगा जब हर बच्चा पढ़ेगा-सिर्फ स्कूल में नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में शिक्षित होगा। अन्यथा, एकल शिक्षक की यह पीड़ा आने वाले भारत की मौन त्रासदी बन जाएगी। शिक्षक दीपक की तरह होते हैं, वे स्वयं जलकर समाज को प्रकाश देते हैं। पर जब दीपक ही अकेला रह जाए, तो अंधकार स्वाभाविक है। अब समय है कि हम इस अंधकार को दूर करने का संकल्प लें, क्योंकि शिक्षा ही राष्ट्र का भविष्य है और शिक्षक उस भविष्य के निर्माता हैं।

सोचने वाली बात है कि एक स्कूल की सारी कक्षाओं को एक शिक्षक कैसे पढ़ाता होगा? छात्र-छात्राएं कैसी और कितनी शिक्षा ग्रहण कर पाते होंगे? शिक्षा का मतलब छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। उन्हें पढ़ाई के साथ पाठ्यसहगामी क्रियाओं का भी ज्ञान दिया जाना जरूरी होता है। लेकिन जब स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक ही नहीं होंगे तो किताबी पढ़ाई कैसी होगी, अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। स्कूल में सिर्फ पढ़ाई ही महत्वपूर्ण नहीं होती। बच्चों का शारीरिक विकास पूरी तरह हो, उसके लिए खेलकूल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों एवं योग-व्यायाम जैसी कक्षाओं की सख्त जरूरत होती है। लेकिन जब शिक्षक ही पर्याप्त नहीं होंगे तो शिक्षा के साथ चलने वाली इन गतिविधियों की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। निस्संदेह, हम छात्रों के बीमार भविष्य की बुनियाद ही रख रहे हैं और ऐसी बीमार बुनियाद पर खड़ा राष्ट्र कैसे स्वस्थ, सक्षम एवं उन्नत होगा? शिक्षा के प्रति यह उपेक्षा हमारे सत्ताधीशों की संवेदनहीनता का भी पर्याय है। शिक्षकों की नियुक्ति में जिस बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामले विभिन्न राज्यों में सामने आए हैं, उससे शिक्षा विभाग की प्रदूषित कार्य संस्कृति का बोध होता है। आखिर क्या वजह है कि देश में प्रशिक्षित शिक्षकों की पर्याप्त संख्या होने के बावजूद स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। यह स्थिति हमारे तंत्र की विफलता को ही उजागर करती है। एक समस्या यह भी है कि शिक्षक जटिल भौगोलिक स्थितियों वाले स्कूलों में काम करने से कतराते हैं। यदि इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हो भी जाती है तो वे दुर्गम से सुगम स्कूलों में अपना तबादला ज्वाइन करने के तुरंत बाद करवा लेते हैं। जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप से लेकर विभागीय लेन-देन की भी शिकायत होती रहती है। यही वजह है कि शहरों व आसपास के इलाकों में स्थित स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती जरूरत से ज्यादा भी देखी जाती है।

कैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सड़कों पर बेरोजगारों की लाइन लगी हैं और स्कूलों में शिक्षकों के लाखों पद खाली हैं। बताया जाता है कि माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालयों में करीब साढ़े आठ लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। इसके बावजूद कि हमारे यहां प्रशिक्षित शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। कहने को तो हमारे गाल बजाते नेता भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं का देश कहते इतराते हैं, लेकिन इन नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि कुंठित होती युवा पीढ़ी के लिये उन्होंने क्या खास किया है? नौकरियों की भर्ती निकलती नहीं है। तीसरी अर्थ-व्यवस्था बनने की ओर अग्रसर देश में ऐसी त्रासद एवं विडम्बनापूर्ण स्थितियों का होना देश के नीति-निर्माताओं एव नायकों के लिये शर्म का विषय होना चाहिए।

वह गांव, जिसे समय ने भुला दिया

सतीश झा

एक प्रधानमंत्री ने कभी दावा किया था कि उसने सौ मिलियन गरीबों के बैंक खाते खुलवाए हैं। मैंने उन खातों की पासबुकें देखीं। पहली एंट्री-जीरो। अगली–कुछ नहीं। दस साल बाद भी वे पासबुकें नीतियों के कब्रिस्तान की निशानियां हैं। एक घर में मुझे चौथी कक्षा का बच्चा मिला। वह एक अंकों का जोड़ कर लेता था, लेकिन दो अंकों में अटक जाता। तीन अक्षरों से आगे उसकी स्पेलिंग टूट जाती। लेकिन उसकी आँखों में उम्मीद थी। वह उम्मीद जो किसी सूखे खेत में भी हरियाली का भरोसा देती है।ज पर सच्चाई यह है कि ऐसे बच्चों के लिए उम्मीद का कोई ठोस कारण नहीं है। क्योंकि हमने ढांचा नहीं बदला, बस भाषण बदले हैं।

आज़ादी के अठहत्तर साल बाद भी भारत में बराबरी की मंज़िल मृगमरीचिका है। हालांकि रास्ता अभी भी है यदि हम उपेक्षा से आगे देखने की हिम्मत करें। मैं पटना से कुछ मील दूर एक गाँव की चौहद्दी पर खड़ा था। गंगा की धुंध अब भी यहां स्मृति की तरह ठहरी रहती है, मानो समय को छोड़ने में हिचकती हो। सुबह का आरंभ था। कौओं की कांव-कांव और हैंडपंपों की खटखट एक दूसरे में घुल रही थी। हैंडपंपों की आवाज़ें, कौओं की कांव-कांव और गलियों में जमा कीचड़, सब मिलकर एक परिचित दृश्य बना रहे थे।

मैंने उम्मीद के साथ उस गांव में कदम रखा, उस उम्मीद के साथ जो तमाम निराशाओं के बावजूद जीती रहती है। सोचा, आज़ादी के इतने साल बाद और इस राज्य पर उन्हीं समुदायों के लोगों के शासन में आने के तीन दशक बाद, अब तो कुछ बदला होगा। अब तो वो बच्चे जिनके बाप-दादा ने सड़कें बनाईं, नालियाँ साफ़ कीं और जिनकी मेहनत से यह देश खड़ा हुआ, उनमें कम-से-कम वही आज़ादी उनके हिस्से भी आई हुई होगी।

लेकिन सच्चाई किसी गुस्से के रूप में नहीं, बल्कि एक थकान-भरे समर्पण के रूप में सामने आई। लोगों की आंखों में एक तरह की शांति थी। मानों उन्होंने हार को मान लिया हो। बातचीत से अंदाज़ा लगा कि उनकी सालाना आय मुश्किल से 18 हजार रू से ज्यादा नहीं थी। मतलब दो सौ डॉलर यानी उतनी, जितनी किसी शहर में चार लोगों का एक डिनर खर्च हो जाता है। गाँव का स्कूल ढहने की कगार पर था, पढ़ाई का स्तर सौ में एक अंक से ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। आँगनवाड़ी का दरवाज़ा तभी खुलता जब ऊपर से निरीक्षण की सूचना मिलती। उस दिन बच्चों को पंक्ति में खड़ा कर दिया जाता, स्लेटें बाँट दी जातीं, एक गीत सिखाया जाता और शिक्षा पूरी हो जाती। बाकी दिन वहाँ सन्नाटा रहता।

गाँव के बाहर खुली नालियाँ, बदबू, मक्खियों का झुंड और गंदगी की मोटी परत, यही रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। एक स्थानीय कार्यकर्ता ने चंदे से जो छोटी पक्की गली बनवाई थी, वही दिखाती थी कि अगर सरकारें काम छोड़ दें तो भी किसी एक व्यक्ति की कोशिश क्या कर सकती है।

यह भारत के दलित हैं। वे लोग जो देश की मेहनत की रीढ़ हैं, लेकिन जिन्हें पहचानने वाला कोई नहीं। उनके वोट से सत्ता बदलती है, लेकिन उनकी ज़िंदगी नहीं। जिनके हाथ दूसरों के घर बनाते हैं, पर अपने घर की छत अब भी टपकती है। उनकी इज़्ज़त हर चुनाव के साथ खोखले वादों में दफ़्न हो जाती है।

एक प्रधानमंत्री ने कभी दावा किया था कि उसने सौ मिलियन गरीबों के बैंक खाते खुलवाए हैं। मैंने उन खातों की पासबुकें देखीं। पहली एंट्री-जीरो। अगली–कुछ नहीं। दस साल बाद भी वे पासबुकें नीतियों के कब्रिस्तान की निशानियां हैं। एक घर में मुझे चौथी कक्षा का बच्चा मिला। चेहरे पर चमक और मुस्कान भरी हुई। वह एक अंकों का जोड़ कर लेता था, लेकिन दो अंकों में अटक जाता। तीन अक्षरों से आगे उसकी स्पेलिंग टूट जाती। लेकिन उसकी आँखों में उम्मीद थी। वह उम्मीद जो किसी सूखे खेत में भी हरियाली का भरोसा देती है। मैंने सोचा, अगर इसे सही माहौल, सही स्कूल और सही शिक्षक मिलें तो यह बच्चा कुछ भी बन सकता है–वैज्ञानिक, कवि, इंजीनियर, या उस भारत का नागरिक जिसे हमने कभी सपना कहा था।

पर सच्चाई यह है कि ऐसे बच्चों के लिए उम्मीद का कोई ठोस कारण नहीं है। क्योंकि हमने ढांचा नहीं बदला, बस भाषण बदले हैं।

यह 2025 का भारत है–जहां मंगलयान भी है, अरबपति भी हैं, लेकिन ऐसे गांव भी हैं जहाँ लोगों की सबसे बड़ी आकांक्षा है किसी तरह जी लेना। अठहत्तर साल पहले अंग्रेज़ों का झंडा नीचे हुआ था, लेकिन बेड़ियां बस और मज़बूत हो गईं। किसी देश की असली पहचान उसके महलों से नहीं, बल्कि उसके सबसे गरीब नागरिक की ज़िंदगी से होती है। हम लोकतंत्र हैं, लेकिन गरीब-अमीर की भयावह असमानता में जीते हैं। हम आज़ादी का वादा करते हैं, पर नियति सौंप देते हैं।

मैंने देखा है कि देश कैसे बदलते हैं–दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों ने भी गरीबी से शुरुआत की थी, पर इरादा पक्का था। उन्होंने समझ लिया था कि शिक्षा कोई दान नहीं बल्कि पूंजी है।

अगर भारत सच में ठान ले कि हर बच्चे को सच्ची शिक्षा मिले, तो एक पीढ़ी में देश बदल सकता है। मेरे हिसाब से अगर हर बच्चे पर सालाना हज़ार डॉलर खर्च किए जाएँ–दस साल लगातार–तो गरीबी और अज्ञान की जड़ें काटी जा सकती हैं।

यह पैसा किताबों या यूनिफ़ॉर्म पर नहीं, बल्कि ऐसे स्कूलों पर लगे जो चलें; ऐसे शिक्षकों पर जो पढ़ाएँ; ऐसे कमरों पर जो बच्चों को प्रेरित करें। इसके साथ पोषण, साफ़ पानी, स्वास्थ्य और इंटरनेट की पहुँच मिले–यानी गरिमा का पूरा ढाँचा। और बारह साल में वही बच्चा दस हज़ार डॉलर सालाना कमाने लायक बन जाए–अपने परिवार का नहीं, देश का भविष्य बदलने वाला नागरिक।

यह सपना असंभव नहीं–यह गणित है। कोरिया ने किया, चीन ने किया, तो भारत क्यों नहीं? समस्या विचारों की नहीं, इच्छा की है। हम जानते हैं क्या करना चाहिए, लेकिन करते नहीं।

अफ़सरशाही अपने ढर्रे पर अटकी है, नेता भाषणों में व्यस्त हैं, और अमीर तबका बस तमाशा देखता है।

विकास अब अनुभव नहीं, शो बन गया है–टीवी पर दिखने वाला इंडिया शाइनिंग का इवेंट।

हमारे नीति-निर्माता डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, लेकिन बिना शिक्षा के युवा पूंजी नहीं, बोझ होते हैं। वो देरी से फटने वाला बम हैं।

हमारी व्यवस्था ने लापरवाही को सामान्य बना दिया है।

अगर दस साल का बच्चा पढ़ना नहीं जानता, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता।

शिक्षक का स्कूल से गायब रहना आम बात है।

सरकारी स्कूल में टूटा शौचालय बस रिपोर्ट की फुटनोट बनता है।

लेकिन जब मूर्तियों, स्टेडियमों और सम्मेलनों की बात आती है तो अरबों रुपए निकल आते हैं।

हम दुनिया को ताक़त दिखाते हैं, पर अपने घर की अंधेरी गलियों में रोशनी नहीं कर पाते।

जब मैं लौटने लगा तो बच्चे पीछे-पीछे आए। उन्होंने पूछा, आप क्या करते हैं?

मैंने कहा, मैं लिखता हूँ।

एक बच्चा बोला, हमारे बारे में लिखिए।

मैंने वादा किया, लिखूँगा।

पर शब्दों से आगे कुछ करना होगा।

हमें एक नैतिक जागरण चाहिए। यह समझ कि भारत की कहानी अधूरी है जब तक इसके दलित बच्चे उपेक्षा में जीते रहेंगे। वे दान के पात्र नहीं, इस देश के बराबर हिस्सेदार हैं।

अगर मैं एक राष्ट्रीय मिशन बना सकता, तो उसका नाम होता–भारत नवजीवन अभियान। राज्य, निजी क्षेत्र और समाज–तीनों मिलकर यह ठानें कि हर गरीब बच्चे पर सालाना हज़ार डॉलर खर्च होंगे–सहायता नहीं, बीज के रूप में। सभी खर्च पारदर्शी और जवाबदेह हों। स्कूल माता-पिता के प्रति ज़िम्मेदार हों, नेता-अफ़सर के नहीं।

शिक्षक की इनाम व्यवस्था परिणाम पर हो, उपस्थिति पर नहीं। भोजन शिक्षा से जुड़ा हो, तकनीक पारदर्शिता से।

सौ ज़िलों में इसे शुरू किया जा सकता है। सीखते हुए, सुधारते हुए इसे पूरे देश में फैलाया जा सकता है।

दस साल में भारत की तस्वीर बदल जाएगी। जहाँ गांवों के बच्चे पढ़ेंगे, सोचेंगे और सपने देखेंगे–जाति या ग़रीबी से परे।

यह कोई कल्पना नहीं, सीधा हिसाब है–नैतिकता का गणित और करुणा की अर्थशास्त्र। इतिहास कभी माफ़ नहीं करता उन लोगों को जो कुछ कर सकते थे लेकिन करना नहीं चाहते थे। अंग्रेज़ चले गए, पर उपेक्षा का शासन अब अपने ही हाथों में है।

असली फांक अब अमीरऔरगरीब या शहरऔरगांव में नहीं, बल्कि सोचने वालों और सोच से वंचित लोगों के बीच है।

और फिर भी उम्मीद बाकी है। हम अपने को बदल सकते हैं–नारे दोहराकर नहीं, उनका अर्थ बदलकर।

गरीबों पर तरस खाकर नहीं, उन्हें सक्षम बनाकर।

जब मैं उस चौथी कक्षा के बच्चे के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे उसके जैसे लाखों बच्चे याद आते हैं–जो बस एक मौके की प्रतीक्षा में हैं। हमारे पास क्या अधिकार है उन्हें उस मौके से वंचित करने का?

सबसे बड़ा पाप है भूल जाना। हम भूल गए हैं कि भारत का मतलब क्या है–ब्रांड नहीं, बाज़ार नहीं–एक नैतिक संकल्प।आजादी अंत नहीं थी, शुरुआत थी। अब हमें वही अधूरी क्रांति पूरी करनी है–गरिमा, अवसर और शिक्षा की क्रांति।

ताकि पटना की झोंपड़ियों के बच्चे गुरुग्राम के स्कूलों के बच्चों के साथ बराबरी से खड़े हो सकें। यह संभव है। मैंने उनकी आँखों में वह संभावना देखी है। भारत का भविष्य किसी बोर्डरूम या चुनावी मंच पर तय नहीं होगा। वह तय होगा उन जगहों पर जहाँ उम्मीद अब भी धीमे स्वर में बोलती है।

शिक्षा,भाषा और संस्कृति देश की समृद्धि का पैमाना

वैश्विक समन्वय की आधारशिला

संजीव ठाकुर

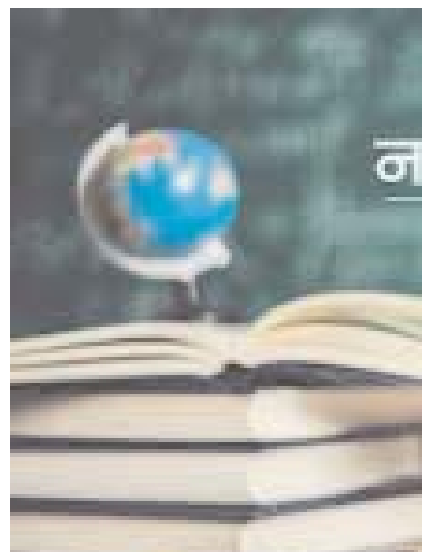

शिक्षा सदैव समाज, संस्कृति और सभ्यताओं के साथ परिवर्तनशील और प्रगतिशील रही है। यह न केवल व्यक्तिगत उन्नति का माध्यम है, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास की आधारशिला भी है। शिक्षा, ज्ञान, कला, साहित्य और संस्कृति को देश-विदेश की सीमाओं में बाँधना संभव नहीं है। यह असीमित भंडार है, जिसमें आकाशीय ऊँचाइयाँ भी शामिल हैं। न केवल इसकी गहराई को नापा जा सकता है, न ही इसकी ऊँचाई को देखा जा सकता है। शिक्षा और ज्ञान की यह विशालता मानव जीवन में अनंत संभावनाओं के द्वार खोलती है।

पूर्वी सभ्यता, विशेषकर भारतीय परंपरा, जहाँ अध्यात्म, वेद, पुराण और योग पर आधारित है, वहाँ पश्चिमी सभ्यता विज्ञान, तकनीकी नवाचार और अनछुई रहस्यमय खोजों पर आधारित है। इन दोनों सभ्यताओं ने अपने-अपने क्षेत्र में मानव जीवन को बदलने वाले अनमोल योगदान दिए हैं। उदाहरण स्वरूप, पश्चिमी विज्ञान ने मानव को चंद्रमा पर पहुँचने का अवसर दिया और आधुनिक तकनीक जैसे हवाई जहाज, इंजन, रेडियो और डिजिटल तकनीक से जीवन को सरल और उन्नत बनाया। वहीं, भारतीय ज्ञान और दर्शन ने योग, आयुर्वेद, ध्यान और जीवन मूल्यों के माध्यम से मानव जीवन में शांति, संतुलन और आत्मसाक्षात्कार की दिशा प्रदान की।

इस प्रकार शिक्षा, भाषा और ज्ञान ने पूर्व और पश्चिम के बीच समन्वय स्थापित किया। पश्चिम ने भारतीय दर्शन, आयुर्वेद और योग को अपनाकर अपनी जीवनशैली में संतुलन पाया, और भारत ने पश्चिम के विज्ञान और तकनीकी ज्ञान को अपनाकर विकास की नई ऊँचाइयों को छुआ। शिक्षा और भाषा सदैव अज्ञानता के तमस में प्रकाश की तरह कार्य करती रही है। यह नवजीवन की विकास धारा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और समाज में सतत प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है।

भारतीय संस्कृति और दर्शन में जैन, बौद्ध, नव्य वेदांत और आधुनिक चिंतन ने समाज में नवयुग की कल्पना को साकार किया। वहीं पश्चिम के दार्शनिक और चिंतक जैसे प्लूटो, अरस्तु, सुकरात, कार्ल मार्क्स और लेनिन ने सामाजिक और राजनीतिक विकास के सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिन्हें पूरी दुनिया ने अपनाया। इस प्रकार, दोनों सभ्यताओं में ज्ञान और विचारों का आदान-प्रदान निरंतर जारी रहा। भारतीय समाज में हमेशा सुधार और नवीन युक्तियों को अपनाने की क्षमता रही है। स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात राजनीति और समाज में हुए परिवर्तन इसका सजीव उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए, गांधीजी ने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन को साकार किया, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने विज्ञान और तकनीक के माध्यम से आधुनिक भारत की नींव रखी। सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की। इन सबके प्रयासों ने भारत को विश्व पटल पर एक नया स्वरूप और पहचान दी।

पाश्चात्य ज्ञान ने हमें अपने आडंबर, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता पर विजय पाने में मदद की। उदाहरण के लिए, वास्तु, जन्मकुंडली और अंधविश्वास से जुड़े कई प्रचलित विश्वासों को आधुनिक विज्ञान और शिक्षा के माध्यम से समाज से दूर किया जा सका। यह स्पष्ट करता है कि शिक्षा और ज्ञान समाज में समग्र सुधार और नवप्रवर्तन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं।

हमारे दैनिक जीवन में भी शिक्षा, भाषा और ज्ञान हमें यह एहसास कराते हैं कि हम अभी भी कितने पीछे हैं और कितनी दूर तक सीखने की आवश्यकता है। ज्ञान का कोई अंतिम स्रोत नहीं होता; यह एक ऐसा समृद्ध भंडार है, जिसमें जितना भी सीखना संभव है, वह निरंतर बढ़ता रहता है। अतः हमें सदैव प्रयासरत रहना चाहिए कि हम पल-पल कुछ नया सीखें–हर व्यक्ति, हर समाज, और हर सभ्यता से।

शिक्षा, भाषा और ज्ञान ही हमें समृद्ध, विकसित और परिवर्तनशील बनाते हैं। परिवर्तनशील जीवन ही नई ऊर्जा, आशा और विकास की नींव रखता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो हर मानव, हर समाज और हर राष्ट्र के लिए सीखने, अपनाने और नवाचार करने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। यही कारण है कि शिक्षा और ज्ञान न केवल व्यक्तिगत उन्नति बल्कि समग्र मानवता के विकास के लिए अनिवार्य हैं।

किसानों तक सस्ते दामों पर ट्रैक्टर पहुँचेंगे : श्री अश्विनी वैष्णव

सोनिक में एकीकृत लॉजिस्टिक्स हब, उर्वरक, खाद्यान्न, सीमेंट और ट्रैक्टरों सहित डोर-टू-डोर लॉजिस्टिक्स और निर्बाध कार्गो आवाजाही प्रदान करेगा

भारतीय रेलवे ने दिल्ली और कोलकाता के बीच सुनिश्चित ट्रांजिट कंटेनर रेल सेवा और मुंबई-कोलकाता मार्ग पर डोर-टू-डोर पार्सल सेवा शुरू की

कॉनकॉर ई-लॉजिस्टिक्स मोबाइल ऐप के साथ निर्बाध प्रथम और अंतिम स्थान तक आवागमन

नई डोर-टू-डोर रेल पार्सल सेवा, मुंबई-कोलकाता मार्ग पर 7.5 प्रतिशत लागत बचत और 30 प्रतिशत तेज़ आवागमन के साथ सड़क परिवहन से बेहतर प्रदर्शन करती है

पीआईबी

केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज सोनिक एकीकृत लॉजिस्टिक्स हब का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया और दो नई डोर-टू-डोर माल ढुलाई और पार्सल सेवाओं को झंडी दिखा कर रवाना किया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डोर-टू-डोर सेवाएँ देश के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि ये दक्षता बढ़ाएँगी और लॉजिस्टिक्स लागत को काफ़ी कम करेंगी। उन्होंने इस बात पर बलर दिया कि उद्योग अब बिना पूरी रेक भरे, एक निश्चित संख्या में कंटेनर अपने गंतव्य तक भेज सकते हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कारखानों और रेलगाडियों के लोडिंग/अनलोडिंग स्थानों के बीच लॉजिस्टिक गैप को अब भारतीय रेलवे व्यापक डोर-टू-डोर सेवाओं के माध्यम से समाप्त करेगा। उन्होंने कहा कि गुड्स शेड या लॉजिस्टिक्स टर्मिनल कंटेनरों को भरने और उतारने की सुविधाओं से सुसज्जित होंगे, जिससे ग्राहकों को नए सेवा मॉडल का पूरा लाभ मिल सकेगा। केंद्रीय मंत्री महोदय ने बताया कि सोनिक यह सुविधा प्रदान करने वाला पहला एकीकृत लॉजिस्टिक्स केंद्र बन गया है। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पहल के अंतर्गत, मल्टीमॉडल सेवाएँ प्रदान करने के लिए 115 टर्मिनल विकसित किए गए हैं, जिससे ग्राहकों को पर्याप्त लाभ होगा।

मुंबई-कोलकाता कॉरिडोर से शुरू होकर, माल की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने और अधिक शहरों तक कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए जल्द ही और सेवाएँ चालू होंगी। केंद्रीय मंत्री महोदय ने कहा कि एक और प्रयोग भी सफल रहा है - किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए ट्रैक्टर जैसे उपकरणों का किफायती दरों पर परिवहन। जिस तरह कार कार्गो को कुशलतापूर्वक ले जाया जाता है, उसी तरह अब ट्रैक्टर और भारी निर्माण उपकरण (जेसीबी) के लिए भी परिवहन सुविधाएँ बढ़ाई जाएँगी।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सतीश कुमार ने इस बात पर बल दिया कि डोर-टू-डोर डिलीवरी पहल रेल-आधारित लॉजिस्टिक्स में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है - जहाँ प्राप्तकर्ता का माल सीधे गोदाम या कारखाने से उठाया जाता है और भारतीय रेलवे द्वारा अंतिम गंतव्य स्थल तक पहुँचाया जाता है। विकसित भारत के लॉजिस्टिक्स विज़न के अनुरूप, यह पहल भारतीय रेलवे के माल के ट्रांसपोर्टर से माल ग्राहकों के लिए एक पूर्ण लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता बनने की शुरुआत का प्रतीक है। उल्लेखनीय है कि भारतीय रेल (भारतीय रेलवे) दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मालवाहक है, जो सालाना 1.6 बिलियन टन माल का परिवहन करता है।

लॉजिस्टिक्स हब/सेवाओं का विवरण:

1. एकीकृत लॉजिस्टिक्स हब के रूप में रेलवे गुड्स शेड (सोनिक, लखनऊ मंडल) रणनीतिक स्थानः यह टर्मिनल लखनऊ से लगभग 50 किलोमीटर और कानपुर से 20 किलोमीटर दूर स्थित है, जो राजधानी और एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के बीच प्रभावी रूप से संपर्क स्थापित करता है।

व्यापक सेवाएँ: यह कानपुर और लखनऊ क्षेत्रों की बढ़ती लॉजिस्टिक्स आवश्यकताओं को पूरा करेगा और ग्राहकों को डोर-टू-डोर लॉजिस्टिक्स, कार्गो के लिए वितरण केंद्र और इन्वेंट्री प्रबंधन सेवाओं सहित संपूर्ण समाधान प्रदान करेगा।

परिचालन प्रबंधनः कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकॉर) सभी टर्मिनल परिचालनों का प्रबंधन करेगा और निर्बाध कार्गो आवाजाही सुनिश्चित करते हुए महत्वपूर्ण प्रथम और अंतिम स्थान तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

कार्गो प्रोफ़ाइलः यह टर्मिनल उर्वरक, खाद्यान्न, सीमेंट और ट्रैक्टर सहित विविध प्रकार की वस्तुओं को लाने-ले जाने के लिए तैयार है।

बुनियादी ढाँचाः इस सुविधा में अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचा है, जिसमें भंडारण, डोर-टू-डोर सेवाएँ और ग्राहकों तथा श्रमिकों दोनों के लिए आवश्यक सुविधाएँ शामिल हैं। 2. सुनिश्चित पारगमन कंटेनर ट्रेन सेवा (दिल्ली से कोलकाता) उद्देश्य और मार्गः यह प्रीमियम सेवा आवागमन समय की गारंटी देती है और सड़क परिवहन का एक विश्वसनीय विकल्प प्रदान करती है। यह मार्ग दिल्ली - आगरा - कानपुर - कोलकाता को जोड़ता है।

मुख्य सेवा मानदंडः

कसुनिश्चित पारगमन समयः 120 घंटे।

कफ्रीक्वेंसीः द्वि-साप्ताहिक प्रस्थान (प्रत्येक बुधवार और शनिवार)। संचालनः इस सेवा में तुगलकाबाद (दिल्ली), आगरा, कानपुर (आईसीडीजी साइडिंग) और कोलकाता (आईसीडीजी साइडिंग) सहित मध्यवर्ती टर्मिनलों पर लोडिंग और अनलोडिंग (लिफ्ट ऑन/लिफ्ट ऑफ) संचालन शामिल है, जिसमें प्रत्येक स्थान पर 6 घंटे का मानकीकृत ठहराव समय है।

आसान बुकिंगः ग्राहक अपनी आपूर्ति श्रृंखला आवश्यकताओं के अनुरूप कई बुकिंग विकल्पों में से चुन सकते हैं: डोर-टू-डोर, डोर-टू-टर्मिनल, टर्मिनल-टू-डोर और टर्मिनल-टू-टर्मिनल।

राज्यपाल श्री डेका ने उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन से की भेंट

रायपुर, लोकशक्ति। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन से भेंट कर विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा की।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में खेल विकास पर दूसरी उच्च स्तरीय कार्यबल की बैठक आज आयोजित हुई

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र को भारत के खेल केंद्र में बदलने के लिए बॉटम-अप दृष्टिकोण और दीर्घकालिक कोचिंग सहभागिता का आह्वान किया

पीआईबी

उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में खेल विकास पर दूसरी उच्च-स्तरीय कार्यबल (एचएलटीएफ) की बैठक आज मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे, मिज़ोरम के खेल मंत्री लालनघिंगलोवा हमार और सभी उत्तर पूर्वी राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रतिनिधि शामिल हुए। यह बैठक 17 अप्रैल, 2025 को आयोजित पहली कार्यबल बैठक के अनुवर्ती के रूप में हुई, जिसका उद्देश्य प्रारंभिक चर्चाओं के बाद हुई प्रगति की समीक्षा करना और खेल प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचे तथा प्रतिभा विकास को सशक्त बनाने हेतु एक व्यापक रोडमैप तैयार करना था। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक एथलेटिक क्षमता और खेलों के प्रति गहरे जुनून को देखते हुए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के भारत के खेल केंद्र के रूप में उभरने की अपार संभावनाओं को रेखांकित किया। उन्होंने व्यापक कोचिंग पैटर्न अपनाने, कोचों की दीर्घकालिक और प्रतिबद्ध भागीदारी सुनिश्चित करने, खेल-आधारित प्रतिभा स्काउटिंग को लागू करने और खेल उत्कृष्टता की एक मज़बूत नींव बनाने के लिए एक बॉटम-अप दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। मंत्री महोदय ने आधुनिक खेल सुविधाओं के विकास, स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने, उच्च क्षमता वाले खेलों की पहचान करने तथा खेल इको-सिस्टम में समग्र विकास और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में जमीनी स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया। चर्चाओं में मौजूदा खेल अवसंरचना की व्यापक समीक्षा, सुविधाओं, प्रतिभा विकास और सुगम्यता में प्रमुख कमियों की पहचान तथा खेल अवसंरचना एवं भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक ढाँचा विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यबल ने प्रतिभा संपन्न और वंचित क्षेत्रों का मानचित्रण, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) और सीएसआर पहलों के माध्यम से निवेश आकर्षित करने और चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए मापनीय लक्ष्यों के साथ एक कार्यान्वयन योग्य रोडमैप विकसित करने पर भी विचार-विमर्श किया।

जीएसटी सुधार 2025 : नगालैंड की अर्थव्यवस्था इससे सभी क्षेत्रों में कैसे लाभ अर्जित करेगी

पीआईबी

जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने के साथ, लगभग 44,000 महिला कारीगरों को नगालैंड के शॉल और वस्त्रों के लिए उच्च आय और व्यापक पहुंच प्राप्त होगी।

5 प्रतिशत जीएसटी के साथ 13,000 से अधिक बांस और बेंत कारीगरों को लाभ हुआ।

5% जीएसटी रोस्टेड और एक्सट्रैक्ट कॉफी को 6-11% सस्ता बनाता है; 2,200 छोटे किसानों और एमएसएमई को लाभ होगा।

आतिथ्य जीएसटी में 5 फीसदी की कटौती, 7,500 रुपये तक के होटल 6 फीसदी सस्ते।

एजेंसी

नगालैंड की अर्थव्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों और उभरते उद्यमों का मिश्रण है। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, हथकरघा, हस्तशिल्प और पर्यटन से जुड़ी है। हाल ही में किए गए जीएसटी सुधार कई उद्योगों में कर दरों को तर्कसंगत बनाकर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हैं। इससे स्थानीय उत्पादकों और उद्यमियों की आय में सुधार होने के साथ ही उत्पादों और सेवाओं को अधिक किफायती बनाने की आशा है।

यह सुधार समावेशी विकास, कारीगरों, किसानों और सूक्ष्म उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए एक परिवर्तनकारी अवसर प्रदान करते हैं और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध नगालैंड को व्यापार और पर्यटन के बढ़ते केंद्र के रूप में स्थापित करते हैं। हथकरघा

जीआई-टैग वाले चाखेसांग शॉल सहित हथकरघा शॉल और वस्त्र, नगालैंड की शिल्पी अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। इनका मुख्य उत्पादन क्लस्टर कोहिमा, फेक (चखेसांग) और दीमापुर के आसपास स्थित है। हाल ही में कोहिमा में एक राज्य एम्पोरियम हब भी स्थापित किया गया है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से महिलाओं के नेतृत्व वाला है, जिसमें बुनकर आवास-आधारित करघों पर काम करते हैं और सूक्ष्म उद्यमों के तौर पर कार्य करते हैं। इस क्षेत्र में लगभग 44,000 व्यक्ति कार्यरत हैं और यह पारंपरिक बुनाई प्रथाओं को संजोए हुए हैं।

उत्पादों को परिधान और स्मारिका बाजारों में और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान विक्रय जाता है, जिससे वैश्विक स्तर पर नगालैंड की विरासत को बढ़ावा मिलता है। निर्यात बाजारों में संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन और कनाडा जैसे गंतव्यों के साथ-साथ कई यूरोपीय देश भी शामिल हैं।

हथकरघा शॉल और वस्त्रों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% करने के साथ, 2,500 रूपए तक की लागत वाली वस्तुएं (पहले सीमा 1,000 रूपए थी) अब लगभग 6.25% सस्ती हो जाएंगी। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा, बुनकरों की आय बढ़ेगी और महिला कारीगरों का समर्थन भी मिलेगा।

पर्यटन सेवाएं नगालैंड में टूर ऑपरेशन, होटल और होमस्टे जैसे पर्यटन क्षेत्रों के जीएसटी सुधारों से लाभान्वित होने की संभावना है। इन गतिविधियों के मुख्य केंद्र कोहिमा, दीमापुर और किसामा का हॉर्नबिल उत्सव हैं, हालांकि पर्यटन सेवाओं का धीरे-धीरे अन्य जिलों में भी विस्तार हो रहा है। हालांकि विदेशी पर्यटन सीमित है परन्तु इनमें भारतीय प्रवासियों के कुल आगंतुकों का हिस्सा अधिक है। आतिथ्य सेवाओं पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% करने के साथ, 7,500 रुपए तक की कीमत वाले होटल के कमरे लगभग 6.25% सस्ते होने की आशा है। इससे सामर्थ्य को बढ़ावा मिलेगा और राज्यव्यापी व्यापक पर्यटन विकास का समर्थन मिलेगा।

बांस और बेंत उत्पाद नगालैंड का बांस और बेंत क्षेत्र सोविमा (चुमौकेदिमा) और दीमापुर में एनबीआरसी केंद्रों में केंद्रित है, जिसमें बांस के क्लस्टर विभिन्न जिलों में फैले हुए हैं। वर्ष 2004 से सक्रिय नगालैंड बांस विकास एजेंसी (एनबीडीए) बांस आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह क्षेत्र लगभग 13,000 लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जिनमें कारीगरों के नेतृत्व वाले एमएसएमई, घरेलू उद्योग और ग्रामीण बढ़ई शामिल हैं। इन उत्पादों का घरेलू बाजारों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और यह फर्नीचर, हस्तशिल्प और पर्यावरण के अनुकूल सजावट की बढ़ती मांग को पूरा करते हैं। फर्नीचर और हस्तशिल्प पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% करने के साथ, कीमतों में 6.25% की गिरावट होने की आशा है, जिससे सामर्थ्य और कारीगर आय में वृद्धि होगी।

नगालैंड कॉफी

जीएसटी सुधारों ने नगालैंड कॉफी के लिए नए अवसरों का सृजन किया है, जिसमें भुनी हुई बीन्स पर दरें 12% से घटाकर 5% और कॉफी के अर्क पर 18% से घटाकर 5% कर दी गई हैं। यह उद्योग मोकोकचुंग, वोखा, मोन, जुन्हेबोटो और तुएनसांग में विरासत और सक्रिय क्षेत्रों के साथ राज्य-व्यापी है। यह क्षेत्र जनजातीय छोटे किसानों द्वारा छायादार भूखंडों की खेती और भूनने और खुदरा बिक्री में लगे एमएसएमई की बढ़ती संख्या द्वारा संचालित है। वर्ष 2022-23 तक, नगालैंड में लगभग 2,200 पंजीकृत कॉफी उत्पादक थे। नगालैंड कॉफी ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में अपनी एक जगह बनाई है। यहां से इसे दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया जैसे देशों को निर्यात किया जाता है।

इलेक्ट्रोफ्लुइड्स और ग्रीव्स कॉटन ने 'मेक इन इंडिया' के लिए D G सेट सेमिनार का आयोजन किया

Truhome FINANCE

ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व नाम श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

मांग सूचना

पंजीकृत कार्यालय: श्रीनिवास टॉवर, पहली मंजिल, दरवाजा नंबर 5, पुराना नंबर 11, दूसरी लेन, सेनाटोफा रोड, अलवरपेट, तेनाम्पेट, चेन्नई-600018
मुख्य कार्यालय: लेवल 3, वॉकहार्ट टॉवर्स, ईस्ट विंग सी-2 ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई) कासी), मुंबई-400051 वेबसाइट: www.truhomefinance.in

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित उधारकर्ता/उधारकर्ताओं ने ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) से प्राप्त ऋण सुविधाओं के मूलधन और ब्याज की अदायगी में चूक की है और उक्त ऋण खातों को गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI ACT) की धारा 13(2) के अंतर्गत उनके अंतिम ज्ञात पते पर मांग नोटिस जारी किया गया था। उक्त मांग नोटिस के अतिरिक्त, उन्हें इस सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया है।
उधारकर्ताओं, प्रतिभूतियों, बकाया राशि, धारा 13(2) के अंतर्गत भेजे गए मांग नोटिस और उसके अंतर्गत दावा की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है।-

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ नाम और पता	सुरक्षित परिसंपत्तियों का संपत्ति पता	डिमांड नोटिस दिनांक एवं देय राशि रु. में.
श्री कुंज लाल पुत्र श्री हीरालाल साहू 2. श्रीमती लक्ष्मी साहू पत्नी श्री कुंज लाल साहू पता : बोलर परिसर के पास, देवरीखुर्द, बिलासपुर, 158, बजरंग पारा, कोहका, इंद्रावती नगर, वार्ड क्रमांक 8, सुपेला, भिलाई, दुर्ग छ.ग.- 490023 ऋण राशि - रु. 10,64,868/- LAN - SLPHRAIP0000395 एनपीए तिथि - 03.10.2025	डायवर्टेड भूमि खसरा नंबर 1046, मौजा खास कोहका, फरीद नगर, पी. एच. नंबर 14, वार्ड नंबर 8, आर.आई.सी. दुर्ग-1, नगर पालिका निगम भिलाई, तहसील एवं जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। माप क्षेत्रफल 2400 वर्ग. फुट। उत्तर - रामलाल देशमुख की भूमि, दक्षिण - 10 फीट चौड़ी गली पूर्व - लोधी की भूमि, पश्चिम - हीरालाल की भूमि ।	डिमांड नोटिस दिनांक - 10-10-2025 रु. 11,63,633/- 09/10/2025 तक तथा साथ में ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत आदि।
1. मेसर्स सोनी कंस्ट्रक्शन (प्रो. श्री रवीन्द्र सोनी पुत्र श्री जैतराम सोनी) 2. श्री रवीन्द्र सोनी पुत्र श्री जैतराम सोनी 3. श्रीमती योगिता सोनी पत्नी श्री रवीन्द्र सोनी पता : डी 95, गुरु घासीदास कॉलोनी, न्यू राजेंद्र नगर, रायपुर छत्तीसगढ़ - 492001 ऋण राशि - रु. 42,00,000/- LAN - SLPHRAIP0000222 एनपीए दिनांक - 03.10.2025	आवासीय भूखंड संख्या D/95 और मकान, खसरा संख्या 379/8, 379/9, 379/14, 379/7 और 379/13 के भाग पर स्थित, गुरु घासीदास गृह निर्माण सहकारी समिति, मौजा टिकरापारा, पीएच संख्या 114, आर.आई.सी. रायपुर-II, तहसील और जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। क्षेत्रफल 2100 वर्ग फुट। उत्तर दिशा - भूखंड संख्या D/96, दक्षिण दिशा - भूखंड संख्या D की सड़क, पूर्व दिशा - भूखंड संख्या D/93-94, पश्चिम दिशा - भूखंड संख्या D की सड़क।	डिमांड नोटिस दिनांक 10-10-2025 44,25,585/- रुपये, 09/10/2025 तक साथ में ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत आदि।

इसलिए आप उधारकर्ताओं से अनुरोध है कि आप इस नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित बकाया राशि का भुगतान करें, साथ ही भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक ब्याज और दंडात्मक ब्याज भी दें, जो देय हो सकता है, ऐसा न करने पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता को उपरोक्त प्रतिभूतियों को लागू करने के लिए SARFAESI अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त संदर्भित प्रतिभूतियों को स्थानांतरित करने से रोका जाता है।

स्थान: दुर्ग और रायपुर
दिनांक: 16-10-2025

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी- ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड
(पहले श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

जिले में 79.7 प्रतिशत विद्यार्थियों का बना अपार आईडी

मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में शिक्षा के डिजिटलीकरण की दिशा में बड़ा कदम - अपार आईडी अभियान हुआ तेज

वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी पहल के तहत अब तक 1.78 लाख छात्रों की अपार आईडी जनरेट

कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने शिक्षा विभाग को शत प्रतिशत विद्यार्थियों का अपार आईडी बनाने के दिए निर्देश

जांजगीर-चांपा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी स्कूली विद्यार्थियों के शत प्रतिशत अपार आईडी बनाए जाने, स्कूलों में ड्राप आउट कम करने, वहीं ग्रास इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाकर शत प्रतिशत करने के निर्देश दिए हैं। इसके अंतर्गत कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन में जिले में पिछले 6 माह से अपार आईडी को लेकर सतत रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है। अब तक जिले में 79.7 प्रतिशत विद्यार्थियों का अपार आईडी (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) बनाया जा चुका है। साथ ही जिले में वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी पहल के तहत अपार आईडी निर्माण कार्य तेजी से जारी है। कलेक्टर ने इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही या कोताही बरतने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार अब तक जिले के कुल 2,24,499 विद्यार्थियों में से 1,78,984 विद्यार्थियों की अपार आईडी बन चुकी है, जो लगभग 79.7 प्रतिशत है। इस उपलब्धि के साथ जिला राज्य स्तर पर आठवें स्थान पर पहुंच गया है। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने शिक्षा विभाग को नियमित रूप से शतप्रतिशत विद्यार्थियों का अपार आईडी बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। जिले के विकासखंड अकालतरा में 79.5 प्रतिशत, बलौदा में 80.2 प्रतिशत, बम्हनीडीह में 84.3 प्रतिशत, नवागढ़ में 77.1 प्रतिशत और पामगढ़ में 79.7 प्रतिशत विद्यार्थियों की अपार आईडी तैयार हो चुकी है। जिले में 467 विद्यार्थियों के लिए अपार निर्माण का रिक्वेस्ट पोर्टल पर दर्ज, 1122 विद्यार्थियों की आईडी रिजेक्ट, जबकि 43,926 विद्यार्थियों की अपार आईडी निर्माण हेतु रिक्वेस्ट अभी नहीं की गई है।

उल्लेखनीय है कि अपार यानी स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री है। यह भारत सरकार की एक डिजिटल पहल है, जिसके माध्यम से प्रत्येक छात्र को 12 अंकों की एक स्थायी डिजिटल पहचान संख्या दी जा रही है। इस पहचान के माध्यम से छात्रों के सभी शैक्षणिक रिकॉर्ड जैसे मार्कशीट, प्रमाणपत्र, डिग्री और उपलब्धियां एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रखी जाती हैं। अपार निर्माण में आने वाली प्रमुख कठिनाइयों में बच्चों के आधार कार्ड का न होना, बायोमेट्रिक अपडेट न होना, जन्म प्रमाण पत्र में त्रुटियों तथा अभिभावकों की उदासीनता प्रमुख कारण हैं। शिक्षा विभाग द्वारा आधार सुधार, डेटा सत्यापन और अभिभावक सहमति पत्र प्राप्त करने हेतु मेगा पीटीएम और मेगा पीआईएम कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि जिले में शत-प्रतिशत विद्यार्थियों की अपार आईडी निर्माण का लक्ष्य शीघ्र पूरा किया जा सके।

नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन की ऑनलाईन तिथि तीन दिन बढ़ी

अब 17 अक्टूबर शाम पांच बजे तक भरे जा सकेंगे आवेदन

जांजगीर-चांपा, संवाददाता। राज्य के नर्सिंग महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवनेदन करने की तिथि तीन दिन बढ़ा दी गई है। विद्यार्थी अब 17 अक्टूबर शाम पांच बजे तक नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन भर सकेंगे। नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग समिति के अध्यक्ष ने इस बारे में सूचना भी जारी कर दी है। इस वर्ष 2025 में काउंसलिंग के जरिए बी.एस.सी. नर्सिंग, एम.एस.सी. नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग, और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साइकियाट्रिक नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। पहले इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर थी जिसे बढ़ाकर 17 अक्टूबर कर दिया गया है। काउंसलिंग, आबंटन और प्रवेश संबंधी सभी जानकारियां चिकित्सा शिक्षा संचालनालय की वेबसाईट www.cgdme.in पर भी उपलब्ध कराई गई है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑनलाईन आवेदन के लिए अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 1 हजार रूपए और अनुसूचित जाति-जनजाति के उम्मीदवारों को 500 रूपए शुल्क जमा करना होगा। ऑनलाईन आवेदन में किसी तरह की गलती हो जाने पर त्रुटि सुधार के लिए 1 हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। त्रुटि सुधार के समय पहले दिए गए ई-मेल एवं मोबाइल नंबर में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा। ऑनलाइन आवेदन के समय ही अभ्यर्थियों को संस्था का चयन करना होगा। इसके लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध रखने होंगे।

अपूर्ण आवेदन या पंजीयन फीस के बैंक गेटवे से जमा नहीं होने पर अभ्यर्थी अपात्र घोषित किये जा सकेंगे। अतः अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से 17 अक्टूबर से 24 घंटे पहले आवेदन भरने की कार्यवाही पूरी कर लेनी चाहिए। पहली काउंसलिंग में आबंटित अभ्यर्थियों को संवीक्षा कराना एवं प्रात्र होना जरूरी होगा। शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य किया गया है। शासकीय नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश नहीं लेने पर अभ्यर्थी अपात्र घोषित किये जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के बाद आगे की कार्यवाही के लिए काउंसलिंग शेड्यूल का अवलोकन विभागीय वेबसाइट पर किया जा सकता है।

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के जन्म दिवस पर पौधारोपण कर ली पर्यावरण संरक्षण की शपथ

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 2025-26 के अंतर्गत आदर्श ग्राम सुरगी में पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सरपंच सुग्रीव साहू, उप सरपंच युवराज साहू, पंचायत सचिव जावंतीन चंदेल, रोजगार सहायक जाम बाई ठाकुर,पंच महेश दिवाकर, पंचायत ऑपरेटर रूपेंद्र चतुर्वेदी, मितानिन बहनें एवं ग्रामीण जनों की उपस्थिति में पौधे लगाए गए। उपस्थित सभी लोगों ने पेड़ों की सुरक्षा और जल संरक्षण की शपथ ली। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि पेड़ हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं, यह न केवल पर्यावरण को संतुलित रखते हैं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए जीवनदायिनी भूमिका निभाते हैं। सभी ग्रामीणों ने संकल्प लिया कि लगाए गए पौधों की देखभाल स्वयं करेंगे ताकि यह एक हरित और स्वच्छ सुरगी का आधार बन सके।

बिर्रा गांव की रश्मि ने बदली अपनी तकदीर, अब 20 हजार महीने की कमाई से बनी आत्मनिर्भर महिला उद्यमी

बिहान का कमाल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सहित अन्य निर्माण कार्यों में सेंटरिंग प्लेट लगाकर रश्मि के हौसले बुलंद

जांजगीर-चांपा

जिले के जनपद पंचायत बम्हनीडीह के बिर्रा गांव की महिला श्रीमती रश्मि कहरा ने यह साबित कर दिखाया है कि अगर हौसला बुलंद हो और अवसर मिले, तो गांव की मिट्टी से भी सफलता की कहानी लिखी जा सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सहित गांव के अन्य निर्माण कार्यों में सेंटरिंग प्लेट की आपूर्ति कर आज वह हर महीने 20 हजार रुपये की आमदनी अर्जित कर रही हैं। यह सफलता उन्हें बिहान योजना और स्व-सहायता समूह के माध्यम से मिली जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी।

श्रीमती रश्मि कहरा ने बताया कि पहले परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च दोनों ही मुश्किल में थे। तब उन्होंने हिम्मत जुटाकर रानी लक्ष्मीबाई स्व सहायता समूह से जुड़ने का निर्णय लिया। समूह के सहयोग और बिहान के मार्गदर्शन से उन्हें आत्मनिर्भरता की राह मिली। उन्होंने सबसे पहले 29 हजार रुपये का बैंक लोन लेकर बच्चों की पढ़ाई में निवेश किया। इसके बाद ग्राम संगठन की सहायता से समुदायिक निवेश कोष से 25 हजार रुपये का ऋण

लिया। इस राशि से उन्होंने 1000 वर्गफीट का सेटरिंग प्लेट तैयार कराया, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य निर्माण कार्यों में किराये पर दिया जा रहा है। इसी से आज उनकी नियमित आय 20,000 रुपये मासिक हो गई है। वे कहती हैं पहले जीवन बहुत कठिन था, लेकिन बिहान समूह से जुड़ने के बाद आत्मविश्वास बढ़ा। अब मैं खुद कमा रही हूँ, बच्चों की पढ़ाई कराती हूँ और दूसरों को भी प्रेरित कर रही हूँ। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त किया।

गांव की साथी महिलाओं के अनुसार, रश्मि की सफलता से अब कई अन्य महिलाएं भी समूहों से जुड़कर प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य आजीविका गतिविधियों में सक्रिय हो रही हैं। बिहान के जिला अधिकारियों का कहना है कि रश्मि की उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि अगर महिला को अवसर, प्रशिक्षण और सहयोग मिले तो वह न केवल अपने परिवार, बल्कि समाज की भी आर्थिक रीढ़ बन सकती है। आज बिर्रा गांव में रश्मि का नाम गर्व से लिया जाता है कभी जो परिवार आर्थिक तंगी में था, वही अब दूसरों की प्रेरणा बन चुका है। सच में, यह है बिहान से निकली उड़ान की मिसाल है जिसने गांव की एक साधारण महिला को आत्मनिर्भरता की पहचान दिलाई।

रेत खदानों के आबंटन हेतु ई-नीलामी की सूचना जारी

7 से 13 नवम्बर तक कर सकते है जमा

जांजगीर-

चांपा / कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला जांजगीर-चांपा द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2025 के नियम-7 के तहत रेत खदानों के आबंटन हेतु इलेक्ट्रॉनिक-नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है।

खनिज अधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में कुल 03 साधारण रेत उत्खनन पट्टा खदानों तहसील बम्हनीडीह के पुछेली, तहसील बलौदा केराकछार-2 तथा तहसील शिवरीनारायण के भोगहापारा-2 का आबंटन किया जाएगा। अर्हता प्राप्त इच्छुक बोलीदाता उक्त इलेक्ट्रॉनिक-नीलामी में भाग ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक-नीलामी हेतु तकनीकी एवं वित्तीय बोली 07 नवम्बर 2025 को प्रातः 10बजे से प्रारंभ होकर 13 नवम्बर 2025 सायं 05.30

बजे तक जमा की जा सकेगी। नीलामी प्रक्रिया केवल एमएसटीसी के ऑनलाइन पोर्टल https//mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/sandcg/inde&.jspds माध्यम से स्वीकार की जाएगी। निविदा की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी एमएसटीसी पोर्टल, खनिज साधन विभाग की वेबसाइट https//chhattisgarhmines.gov.in, जिला कार्यालय की वेबसाइट https//janjgir-champa.gov.in/en/ तथा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला जांजगीर-चांपा के साथ-साथ संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत भवन के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिबद्ध : आलोक सिंह ठाकुर

आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को किया संबोधित

स्वदेशी अपनाने लिए सभी को किया प्रेरित*

जांजगीर चाम्पा - कार्यक्रम अभियान की शुरुआत भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय डा श्यामप्रसाद मुखर्जी के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलित कर व माल्यार्पण कर शुरुआत की उसके पश्चात कार्यकर्ताओ द्वारा अपने अतिथिगणो का स्वागत सत्कार किया गया स्वागत भाषण देते हुए जिलाध्यक्ष अंबेश जांगड़े ने कहा कि पुरे जिले के अलग अलग तीनो विधानसभा मे आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का विधानसभा स्तरीय सम्मेलन आयोजित हो रहा है हमारे कार्यकर्ता सभी मंडलो मे प्रभारी बनकर जा रहे है और इस सम्बन्ध मे उनसे बातचीत कर आम जन को इस अभियान से जुड़ने की अपील कर रहे है

किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम मे जांजगीर चाम्पा विधानसभा स्तरीय सम्मेलन मे उपस्थित कार्यकर्ताओ को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के लोग प्रतिबद्ध है हमारे मजदूर पहले स्वदेशी सामग्री बनाकर पुरे विश्व मे निर्यात करते थे लेकिन मुगल अंग्रेजी शासन और कांग्रेस की गलत नीतीयो के कारण हम पिछड़ेपन का शिकार हो गए नरेंद्र मोदी जी लगातार हम देशवासियो से वोकल फार लोकल की बात कर रहे है

उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन के माध्यम से विश्व में एक महत्वपूर्ण विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है। अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी उत्पाद अपनाकर और भारतीय उद्यमियों और कारीगरों का समर्थन कर हम एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दे सकते हैं।

आगे श्री ठाकुर ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से भारत में व्यापार व्यवसाय समृद्ध रहा है। अनुशासित जीवन पद्धति जियो और जीने दो के विचार का अनुसरण करने के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज सदैव पुष्पित पल्लवित होता

रहा है। समाज में विद्यमान धर्मादा की परम्परा से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जनकल्याण गतिविधियों का संचालन होता था। पिछली सरकारों की लाइसेंस, कोटा, परमिट जैसी नीतियों से देश की मुद्रा का अवमूल्यन हुआ और समाज द्वारा संचालित व्यवस्थाओं में भी शासकीय हस्तक्षेप के दुष्परिणाम सामने आने लगे उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपई ने अपने अतीत को गौरव के साथ देखने की दृष्टि दी और संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर भारतीय बौद्धिक सामर्थ्य को विश्व में स्थापित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और पहल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख और आर्थिक सामर्थय स्थापित हुई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी किसानों के हितैषी होने के साथ ही मजदूरों, व्यापारियों सहित सभी वर्गों के हित चिंतक हैं। उनके मार्गदर्शन में व्यापार-व्यवसाय और कर व्यवस्था में लागू सरल और पारदर्शी नीतियों ने आम आदमी के जीवन को सुगम बनाया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर छग का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में उद्योग तथा निवेश गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए जारी गतिविधियों से स्वदेशी को बल मिलेगा आगामी दिनों में आ रहे त्यौहारों में स्वदेशी सामग्री का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए उपस्थित कार्यकर्ताओ को प्रेरित किया।

हमें हर घर स्वदेशी का मंत्र अपनाकर भारत को सशक्त राष्ट्र बनाने में योगदान देना होगा- *नारायण चंदेल*

श्री चंदेल ने कार्यकर्ताओ को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता अब भारत के राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा बन चुकी है। आज पूरी दुनिया भारत को नए नजरिए से देख रही है। यह हमारे आत्मविश्वास, स्वदेशी भावना और संगठन शक्ति का परिणाम है प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भारत के पुनर्जागरण का मार्ग है। जब हम अपने स्थानीय उद्योगों, कारीगरों और संसाधनों को प्राथमिकता देंगे, तभी भारत सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर बनेगा। हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी केवल नारा नहीं, बल्कि भारत के उत्थान की दिशा में एक विराट आंदोलन है भाजपा का उद्देश्य केवल राजनीति नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है। हमारे छग की धरती में अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें स्वदेशी दृष्टिकोण से सशक्त कर प्रदेश को आत्मनिर्भर भारत का मजबूत स्तंभ बनाया जा सकता है। सम्मेलन के समापन पर मौजूद सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया और यह प्रण किया कि वे समाज के हर वर्ग तक आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग का संदेश पहुंचाएंगे। सभी ने इस अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप देने का निर्णय लिया।इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष गुलाब चंदेल कार्तिकेशवर स्वर्णकार प्रदीप नामदेव किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री राकेश तिवारी जिला महामंत्री नंदनी रजवाड़े अमर सुल्तानिया अर्चना देवांगन अभिमन्यु राठौर पुष्पेंद्र सिंह समीर शुक्ला आशुतोष गोस्वामी पंकज अग्रवाल संतोषी दुबे राम खुबवानी प्रदीप शराफराम खुबवानी मीरा पत्की शिव अंगत बिंझवार विवेका गोपाल हितेश यादव ध्वजाराम साहु समर्थ सिंह संतोष थवाईत सनत पांडेय खमहन तिवारी बलराम पांडेय रवि पांडेय शैलेंद्र पांडेय मंगतुराम शर्मा मोहन यादव संजय राठौर प्रदीप सोनी उमेश राठौर अनिल शर्मा चमन शिव सिंह महादेव साहु उमा सोनी प्रतिमा डहारे डा धनेशवरी जाग्रति पूजा राठौर संजीता माली रिया यादव संगीता पांडेय विवेक सिंह रामेश्वर पटेल निरंजन कोसले रितेश अग्रवाल प्रशांत मिश्रा राकेश रूपवानी दिव्यांश चंदेल चंद्रकांत रात्रे गोलू दुबे चुन्नी राठौर सोनु यादव सुशील सिंह दिनेश राठौर प्रदीप राठौर सहित कार्यकर्त्ता उपस्थित थे

रेलवे ट्रैक पर शिक्षक का क्षत-विक्षत शव मिला, आरपीएफने बताया सुसाइड

कोरबा।

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में रविवार रात एक दर्दनाक घटना सामने आई। कुसमुंडा थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर एक शिक्षक का शव क्षत-विक्षत हालत में मिला। मृतक की पहचान संतोष नायर (50 वर्ष) के रूप में हुई है, जो दीपका ऊर्जा नगर में अपने परिवार के साथ रहता था। जानकारी के अनुसार, संतोष नायर बीकन इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षक थे और करीब दो साल पहले परिवार सहित केरल से कोरबा आए थे। रविवार रात उनका शव ट्रैक पर मिला, जिसमें सिर धड़ से अलग होकर दूर पड़ा था और शरीर कई टुकड़ों में बंट गया था।

घटना की जानकारी मिलते ही आरपीएफमौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्राथमिक जांच में आरपीएफ ने इसे आत्महत्या का मामला बताया है, हालांकि अभी तक मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। इस दर्दनाक घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है।

खास खबर

गला घोंटने के कारण दम घुटने से महिला की मौत, आरोपी गिरफ्तार

कोरबा। जिले के थाना दर्री के मर्ग क्रमांक 41/2025 धारा 194 बीएनएसएस की जांच के दौरान मृतिका मंजू राव पति सुनील राव उम्र 35 साल पता पुष्प पल्लव कॉलोनी दर्री थाना दर्री जिला कोरबा (छ.ग.) की मृत्यु से संबंधित पी.एम. रिपोर्ट प्राप्त हुआ जिसमे डॉक्टरो के द्वारा उसकी गला घोंटने के कारण दम घुटने से मृत्यु होना लेख किये जाने पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितिश ठाकुर,नगर पुलिस अधीक्षक दर्री विमल कुमार पाठक, द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किये जाने पर थाना प्रभारी दर्री उपनिरीक्षक रश्मि थामस के मार्गदर्शन मे संदेही मृतिका का पति सुनील राव को पुलिस अभिरक्षा मे लेकर पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन लिया गया। जिसके द्वारा घटना दिनांक को मृतिका का गला दबाकर हत्या करना स्वीकार किया गया। मामले मे आरोपी सुनील राव के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से आरोपी को दिनांक 12.10.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय से न्यायिक रिमाण्ड प्राप्त कर उपजेल कटघोरा निरूद्ध किया गया है।

उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियो के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी दर्री उप निरीक्षक रश्मि थामस, सउनि सिमसोन मिंज, सउनि संतोष कुमार ताण्डी, आरक्षक अशोक चैहान, उमेश खूंटे, रामस्वरूप कश्यप, भागीरथी यादव, महिला आरक्षक कविता पैकरा एवं सैनिक हिमांशु तिवारी की सराहनीय भूमिका रही।

गौ माता चौंक पर जाम की समस्या से लोग परेशान, व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित

कोरबा। मानिकपुर शहर के गऊ माता चैक पर बढ़ते वाहनों के दबाव के कारण रोजाना लंबा जाम लग रहा है, जिससे आम जनता और वाहन चालक दोनों परेशान हैं। नागरिकों का कहना है कि भारी वाहन आने-जाने के कारण यातायात सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा और चैक पर लंबा जाम बन जाता है। स्थानीय लोग और व्यापारी नगर प्रशासन से अपील कर चुके हैं कि चैक पर यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए जल्द प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि आमजन और व्यापारिक गतिविधियों को होने वाली असुविधा दूर हो सके। नागरिकों का कहना है कि यदि प्रशासन ने समस्या का समाधान नहीं किया, तो यह जाम रोजमर्रा की जिंदगी और नगर की व्यावसायिक गतिविधियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

खेल हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाता है, खेल से मिलती है आगे बढ़ने की प्रेरणा : उद्योग मंत्री

25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ

कोरबा संवाददाता।

छत्तीसगढ़ के उर्जाधानी कोरबा के सीएसईबी फुटबॉल ग्राउंड में प्रदेश सरकार के वाणिज्य, उद्योग व श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन द्वारा दीप प्रज्वलित कर 25वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कटघोरा विधायक श्री प्रेमचंद पटेल, नगर पालिक निगम महापौर कोरबा श्रीमती संजूदेवी राजपूत, सभापति श्री नूतन सिंह ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह गौरव की बात है कि इस राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता के मेजबानी की जिम्मेदारी कोरबा जिले को पुनः मिली है। उन्होंने कहा कि खेल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खेल हमें जीवन मे बहुत कुछ सिखाता है, खेल में हार जीत लगा रहता है, इसमें निराश होने की जरूरत नही है, बल्कि अपनी गलतियों एवं कमियों को सुधार कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। मंत्री श्री देवांगन ने कहा है कि खेल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिससे शारीरिक के साथ ही बौद्धिक विकास भी होता है। खेल से हम स्पर्धा, समर्पण, मेहनत और टीम भावना सीखते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से अलग अलग क्षेत्रो के लोगों को एक दूसरे की संस्कृति, रीति रिवाजों से परिचित होने व जुड़ने का मौका है। उन्होंने कहा कि आप सभी यहां से एक सुखद यादें एवं अनुभव लेकर जाएंगे जो जीवन पर्यन्त आपके काम आएंगी। मंत्री श्री देवांगन ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि आप सभी देश का आने वाला कल है। शिक्षा के साथ साथ खेल एवं अन्य विधाओं में आगे बढ़ने का सभी प्रयास करते रहे। उन्होंने सभी प्रतिभागियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खेल भावना के साथ हिस्सा लेने एवं अपना सर्वोच्च प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित किया। जिससे वे आगे चलकर नेशनल जैसे बड़े प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खेल कौशल दिखा सकें एवं अपने परिवार का नाम रौशन कर सकें। विधायक कटघोरा श्री पटेल ने कहा कि खेल जीवन के लिए बहुमूल्य है। खेल से व्यक्ति को अपने प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलता है। जीवन मे धैर्य व अनुशासन के साथ कठिन परिश्रम करने से निश्चित ही अच्छा परिणाम मिलता है। इसलिए आप सभी खेल का आनंद ले, अपने बेहतर प्रदर्शन से जीत हासिल करें। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को अपने-अपने संभाग का प्रतिनिधित्व करने और ऊर्जा के साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित किया और बेहतर प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दी।

शुभारंभ कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री देवांगन ने 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का विधिवत् उद्घाटन और ध्वजोत्तोलन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने सभी खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के निर्धारित नियमों एवं विधियों का निष्ठापूर्वक पालन करने तथा देश एवं खेल के गौरव के लिए सच्चे खिलाड़ी भावना के साथ भाग लेने की शपथ दिलाई। शुभारंभ अवसर पर छात्र-छात्राओ द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति दी गई एवं पांचों संभाग के खिलाड़ियों द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने खेल प्रतिवेदन प्रस्तुत किया साथ ही अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि इस राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में प्रदेश के पांचों सभांग बस्तर, दुर्ग, रायपुर, सरगुजा एवं बिलासपुर संभाग के प्रतिभागी शामिल हैं। 12 से 15 अक्टूबर तक चलने वाले चार दिवसीय राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के दो विधा की प्रतियोगिता का आयोजन होगा। जिसके अंतर्गत क्रिकेट, तैराकी, हॉकी, व्हॉलीबाल, वाटर पोलो बालक/बालिका प्रतियोगिता शामिल है।

बिलासपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्पलाइज एसोसियेशन का 12 वां वार्षिक सम्मेलन संपन्न

अध्यक्ष संगीता झा और महासचिव राजेश शर्मा चुने गए

बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि आत्मघातीरूधर्मराज

कोरबा।

बिलासपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्पलाइज एसोसियेशन का 12 वां वार्षिक सम्मेलन कोरबा के पाटीदार भवन में संपन्न हुआ काम. छतराम सूर्यवंशी मंच और काम. बी.सान्याल के नाम पर नगर का नाम रखा गया सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कामरेड धर्मराज महापात्र सहसचिव ए.आई.आई.ई.ए. एवं महासचिव सी.जेड.आई.ई.ए. और विशिष्ट अतिथि काम. सुरेंद्र शर्मा महासचिव आर.डी.आई.ई.यू. स्वागत समिति के अध्यक्ष काम. वी एम मनोहर,सीटू राज्य अध्यक्ष एस एन बैनर्जी विशेष रूप से उपस्थित थे।

सम्मेलन की शुरुवात विशाल रैली से शुरू हुई जो कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर से निकली रैली के बाद बिलासपुर डिवीजन की अध्यक्ष संगीता झा ने ध्वजारोहण किया जिसके बाद सम्मेलन का खुले अधिवेशन की शुरुवात स्वागत समिति के अध्यक्ष वी एम मनोहर ने किया। अध्यक्षीय उद्बोधन संगीता झा ने रखा उसके बाद धर्मराज महापात्र सहसचिव ए.आई.आई.ई.ए. ने सत्र का उद्घाटन भाषण दिया कामरेड धर्मराज महापात्र ने कहा कि आल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलाइज एसोसियेशन भारतीय जीवन बीमा में कार्यरत 85 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों का नेतृत्व करता है राष्ट्रीयकरण के पूर्व देश में 245 से अधिक बीमा कंपनियां काम कर रही थी,जो पालिशीधारकों के हितों का संरक्षण के स्थान पर बीमा में कमाये गए मुनाफे को अपनी घाटे में चलने वाले व्यवसाय का संरक्षण कर पालिसीधारकों के धन को हड़पने के खेल में लगी थी और यही कारण था कि पालिसीधारकों के हित में बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य भी तय किए गए थे जिसमें जनता की बचत को राष्ट्र कल्याण में लगाना,उन्हें बीमा सुरक्षा प्रदान करना तथा सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों को संचालित कर रोजगारों के सृजन का भी कार्य शामिल था। वर्तमान सरकार एक तरफ स्वदेशी का नारा दे कर स्वदेशी अपनाने की बात कर रही है तो दूसरी ओर उसके ठीक विपरीत काम करते हुए उन्हें आमंत्रित कर रही है यह दोहरा चरित्र अनुचित है। उन्होंने आगे कहा कि सतत सेवानिवृत्ति के फ्लस्वरूप कर्मचारियों पर कार्य का दबाव सतत रूप से बढ़ रहा है। निगम का व्यवसाय 410: बढ़ा है वहीं कर्मचारियों की संख्या 43: कम हुई है। आज उद्योग में नयी भर्ती की लड़ाई सरकार के नीतियों के खिलाफलड़ाई हो गई है। सरकार निजीकरण के नाम पर तमाम सार्वजनिक उपक्रमों को निजी घरानों को सौंपने का कार्य कर रही है।

दो दिवसीय सम्मेलन में बीमा संशोधन विधेयक वापस लेने सहित 16 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए और सभी विषयों पर गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श करके संघर्ष की रूप रेखा का निर्माण की रूपरेखा बनाई गई।

कलेक्टर अजीत वसंत की सराहना,

कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में कोरबा का प्रदर्शन रहा उत्कृष्ट

कोरबा-रायपुर मंत्रालय में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में कोरबा जिले के कार्यों की विशेष सराहना की गई। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन में कोरबा ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कोरबा का मॉडल अन्य जिलों के लिए प्रेरणादायक है। गौरतलब है कि पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने कलेक्टर अजीत वसंत के कामकाज पर सवाल उठाते हुए उनके हटाए जाने की मांग की थी, लेकिन अब सरकार ने उनकी उपलब्धियों की सराहना करते हुए पीठ थपथपाई है।

कांफ्रेंस के दौरान कलेक्टर अजीत वसंत ने बताया कि जिले की विशेष पिछड़ी जनजातियों बैगा और कोरवा समुदाय के बीच योजना को प्राथमिकता से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि डीएमएफ (जिला खनिज फाउंडेशन) की मदद से 700 घरों में, जो पीएम जनमन योजना के तहत बनाए जा रहे हैं, सूर्य घर योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रति घर 60 हजार रुपए की सहायता दी जा रही है, जिसमें से 45 हजार रुपए सरकारी सब्सिडी और 15 हजार रुपए डीएमएफ की राशि शामिल है।

एसईसीएल गेवरा परियोजना में लिपिक और ठेकेदार के बीच मारपीट, शिकायत पर काउंटर केस दर्ज

कोरबा संवाददाता

एसईसीएल की गेवरा परियोजना स्थित गोल ऑफिस में शनिवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब किसी कार्य को लेकर लिपिक और ठेकेदार के बीच कहासुनी ने मारपीट का रूप ले लिया। घटना के बाद दोनों पक्षों को चोटें आईं और पुलिस ने दोनों की शिकायत पर काउंटर केस दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। दीपका थाना पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शनिवार दोपहर लगभग 1 बजे शारदा विहार कॉलोनी निवासी लिपिक अंकित बोकार्ड और ठेकेदार अंकित जायसवाल के बीच किसी कार्य से जुड़ी बात को लेकर विवाद हो गया। प्रारंभ में यह विवाद मौखिक बहस तक सीमित था, लेकिन देखते ही देखते दोनों के बीच झूमाझटकी और फिर मारपीट की नौबत आ गई। ऑफिस परिसर में मौजूद कर्मचारियों ने किसी तरह बीच-बचाव कर स्थिति को संभाला। सूत्रों के अनुसार, झगड़े के दौरान दोनों को चोटें आईं, जिसके बाद उन्होंने एक-दूसरे के खिलाफ दीपका थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों की रिपोर्ट के आधार पर धारा 294, 323, 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस का कहना है कि घटना की पूरी जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि विवाद के वास्तविक कारण और जिम्मेदार पक्ष का पता लगाया जा सके।

छत्तीसगढ़ सशक्त दिव्यांगजन संघ का सम्मेलन संपन्न

रोजगार के साथ प्रधानमंत्री आवास की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का लिया निर्णय

कोरबा संवाददाता।

छत्तीसगढ़ सशक्त दिव्यांगजन संघ का सम्मेलन सीटू कार्यालय कोरबा में आयोजित हुआ सम्मेलन में मुख्य अतिथि सीटू के राज्य उप महासचिव वी एम मनोहर थे। सम्मेलन में सीटू के राज्य अध्यक्ष एस एन बैनर्जी उपस्थित थे। सम्मेलन की अध्यक्षता पन्नालाल बांधे ने की उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांगजनो को रोजगार में प्राथमिकता मिले एवं खदानों में काम के दौरान दुर्घटना में शिकार हुए दिव्यांगजनो को उसी खदानों में काम पे रखा जाए जिससे उनके आगे का जीवन चल सके। इसी के साथ दिव्यांगजनो को कई प्रकार से आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है और शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिव्यांगजनो को प्राथमिकता के आधार पर आवास योजना का लाभ मिल सके।

संघ के महासचिव संतोष बंजारे ने महासचिव प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई जिसका सभी ने समर्थन किया। संघ के सचिव प्रदीप चंद्रा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। सम्मेलन के अंत में आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा कर दिव्यांगजनो की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का भी निर्णय लिया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अमित गुप्ता, सुखेंदु घोष, राजेश नागराज, धनंजय चंद्रा, रामाधार चंद्रा, जी डी महंत उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना : उजाले से उपजता आत्मविश्वास

'बिजली नहीं, उम्मीदें पैदा कर रहा सूरज, कोरबा के घरों में उजाले से आई समृद्धि'

कोरबा भारत आज ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति का नेतृत्व कर रहा है, जो न केवल वर्तमान की जरूरतों को पूरा कर रही है, बल्कि आने वाले दशकों के लिए एक स्थायी और स्वच्छ भविष्य की नींव भी रख रही है। हरित ऊर्जा और आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए ठोस कदम अब केवल नीतियों की पंक्तियों में नहीं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन में चमकते उजालों में दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आरंभ की गई प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना इसी परिवर्तन की एक अद्भुत मिसाल है। यह योजना भारत के हर नागरिक को सूरज की असीम ऊर्जा से जोड़कर एक ऐसा भविष्य गढ़ रही है, जहाँ हर घर ऊर्जा का उत्पादक बने और हर नागरिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक। इस योजना का मूल विचार सरल, परंतु अत्यंत प्रभावशाली है हर घर की छत पर सौर ऊर्जा, हर परिवार में बचत और स्वावलंबन।

भारत जैसे सूर्य-प्रधान देश में जहाँ वर्षभर पर्याप्त धूप उपलब्ध रहती है, वहाँ सौर ऊर्जा केवल विकल्प नहीं, बल्कि अवसर है। इस अवसर को साकार रूप देने के लिए भारत सरकार ने सशक्त तकनीकी, वित्तीय सहायता और पारदर्शी प्रक्रिया का समावेश किया है। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के अंतर्गत नागरिकों को अपनी छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है। इससे न केवल बिजली की आवश्यकताएँ पूर्ण हो रही हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजकर आमदनी का भी रास्ता खुल रहा है। योजना का यह स्वरूप नागरिकों को उपभोक्ता से उत्पादक की भूमिका में लाता है। यह बदलाव न केवल व्यक्तिगत स्तर पर राहत देता है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। आज भारत के अनेक शहरों और गांवों में यह योजना लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। कोरबा जैसे औद्योगिक क्षेत्र में, जहाँ पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की पहचान रही है, अब सूरज की रोशनी ने स्वच्छ और हरित ऊर्जा का नया अध्याय रच दिया है। यहाँ के नागरिक न केवल पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त बन रहे हैं। कोरबा जिले के दो परिवारों श्री आयुष अग्रवाल और श्री अजय राज बेन की कहानियाँ इस योजना की सफलता को जीवंत रूप से दर्शाती हैं। दोनों की परिस्थितियाँ भले ही अलग रही हों, लेकिन दोनों ने सूरज की शक्ति से अपनी दुनिया को नया उजाला दिया है।

आयुष अग्रवाल कोरबा के डीडीएम रोड पर रहते हैं। उनका संयुक्त परिवार है, जहाँ आधुनिक घरेलू उपकरणों की जरूरतें अधिक हैं। पहले उन्हें हर महीने बिजली के बढ़ते खर्च को लेकर चिंता रहती थी। फिर उन्हें प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की जानकारी मिली, और उन्होंने इस अवसर को अपनाने का निर्णय लिया। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह सरल और पारदर्शी रही। जिला प्रशासन और ऊर्जा विभाग के मार्गदर्शन से कुछ ही समय में उनके घर की छत पर सोलर पैनल लग गए। आज उनके घर में सूरज की रोशनी से चलने वाले पंखे, कूलर, फ्रिज और ए.सी. सब सहजता से काम कर रहे हैं। अब बिजली बिल लगभग आधा हो गया है और वही पैसा बचत के रूप में परिवार की आर्थिक स्थिरता को बढ़ा रहा है।श्री अग्रवाल ने कहा अब हमें सूरज की हर किरण में बचत नजर आती है। हर महीने की चिंता अब गर्व में बदल गई है। वे बताते हैं कि योजना की प्रक्रिया आसान थी और सरकार की ओर से मिली तकनीकी सहायता ने पूरे अनुभव को भरोसेमंद बनाया। आज उनका परिवार पूरी तरह सौर ऊर्जा पर निर्भर है और पर्यावरण संरक्षण में भी सक्रिय योगदान दे रहा है।वहीं, दूसरी ओर दादरखुर्द के निवासी श्री अजय राज बेन की कहानी भी उतनी ही प्रेरक है। भारतीय वायुसेना में देश सेवा के बाद उन्होंने जीवन के नए चरण में समाज को कुछ लौटाने का निश्चय किया। वर्ष 2024 में जब उन्होंने अखबार में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के बारे में पढ़ा, तो तुरंत इस दिशा में कदम बढ़ाया। उन्होंने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट का सोलर पैनल स्थापित कराया, सरकार से मिली सब्सिडी और त्वरित प्रक्रिया ने स्थापना को सहज बना दिया।

महिला एवं बाल विकास विभाग की डीपीएम रेणु प्रकाश को शासन ने हटाया

कोरबा 1 महिला एवं बाल विकास विभाग की गतिविधियां सुर्खिया बनने और जिला कार्यक्रम अधिकारी रेणु प्रकाश के खिलाफलगातार शिकायत के बाद संचालनालय महिला एवं बाल विकास छत्तीसगढ़ द्वारा एक्शन लिया गया है। महिला एवं बाल विकास के संचालक पदुम सिंह एल्मा के हस्ताक्षर से आदेश पत्र जारी हुआ जिसमें रेणु प्रकाश को नवीन पदस्थापना स्थल कोण्डागांव में कार्यभार ग्रहण करने के लिए एकतरफा भारमुक्त किया गया है।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग गरियाबंद,(छ.ग.)
द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा विज्ञप्ति क्र. 3713/NIT - 8 /व.ले.लि./2025–26 — गरियाबन्द दिनांक 13/10/2025

1. निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि:– 29.10.2025 अपरान्ह 5.30 बजे तक
2. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निविदायें प्राप्त करने की अंतिम तिथि :– 06.11.2025 अपरान्ह 5.30 बजे तक
3. निविदा खोलने की तिथि :– 07.11.2025 पूर्वान्ह 11.30 बजे तक
4. निविदा प्रपत्र की कीमत :– 750/
5. कार्य की अवधि :– 02 वर्ष माह
6. निविदा प्रपत्र :– A
7. ठेकेदार की श्रेणी :– ई–पंजीयन के अंतर्गत द–श्रेणी से अ–श्रेणी तक

एन. आई.टी. /निविदा क्रमांक	कार्य का नाम /No of Calls	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)/अमानत राशि/बैंक साल्वेंसी (रू.में)
1	2	3
8/T0068	नवीन व्यवहार न्यायालय भवन देवभोग के प्रवेश द्वार में गार्ड रूम का निर्माण कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	1.82 2000.00 30000.00

निविदा संबंधी शर्तें विभागीय वेबसाईट www.pwd.cg.nic.in में Live Tender के अंतर्गत निविदा प्रपत्र मे उपलब्ध है। इनका अवलोकन संबंधित संभाग कार्यालय मे किया जा सकता है।

G-252604201/2

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग (भ/स)
संभाग गरियाबंद

मुख्यमंत्री के निर्देशों पर त्वरित अमल सुनिश्चित करें : मुख्य सचिव विकास शील

रायपुर। मुख्य सचिव श्री विकास शील ने कहा कि कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा दिए गए निर्देशों पर त्वरित और प्रभावी अमल सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी विभागीय सचिवों को सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सहित अन्य प्राथमिक क्षेत्रों के लिए ठोस एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव आज मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के भारसाधक सचिवों के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में शामिल विभागों के एक्शन प्लान्स की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन कार्यों का शिलान्यास किया जा चुका है, उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण कर लोकार्पण सुनिश्चित किया जाए।बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना तथा जेम पोर्टल के माध्यम से शासकीय विभागों में की जा रही खरीदी की प्रक्रिया पर प्रस्तुतीकरण दिया। इसी प्रकार, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव एवं आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. रवि मित्तल ने जनसम्पर्क विभाग द्वारा शासन की योजनाओं के प्रचार-प्रसार से संबंधित गतिविधियों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह एवं जेल श्री मनोज कुमार पिंगुआ, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सहित सभी विभागों के सचिव उपस्थित थे।

बिजली कंपनी कर्मचारियों की हड़ताल पर सख्त हुआ प्रशासन, अनुपस्थित कर्मियों की सेवा होगी बाधित

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर प्रबंधन ने कड़ा रुख अपनाया है। कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में चल रही हड़ताल में शामिल होने वालों की गैरहाजिरी को 'ब्रेक इन सर्विस' माना जाएगा, जिससे उनका वेतन काटा जाएगा और यह सेवा में अंतराल के रूप में दर्ज होगा। ट्रांसमिशन विंग के मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) ए.एम. परियल द्वारा जारी आधिकारिक परिपत्र में तीनों पावर कंपनियों ङ्क उत्पादन, वितरण और ट्रांसमिशन ङ्क के विभाग प्रमुखों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों के मुताबिक, जो कर्मचारी सामूहिक अवकाश या हड़ताल में भाग लेंगे, उनकी अनुपस्थिति को अनधिकृत माना जाएगा और उन दिनों का वेतन नहीं दिया जाएगा। यह आचरण प्रबंधन द्वारा कदाचार की श्रेणी में रखा गया है, जिस पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, हड़ताल में भाग लेना या अन्य कर्मचारियों को इसके लिए प्रेरित करना दीर्घकालीन दुराचार माना जाएगा, जिस पर कड़ी सजा संभव है। मुख्य अभियंता परियल ने यह भी बताया कि सभी विभागाध्यक्षों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार कर शीघ्र मानव संसाधन विभाग को भेजें। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उपलब्ध स्टाफ और संसाधनों के जरिए सेवाएं बाधित न हों और कार्य संचालन सुचारू रूप से जारी रहे।

अंग्रेजी हुकूमत काल के जनजातीय विद्रोहों पर आधारित संग्रहालय को दिया जा रहा अंतिम स्वरूप

रायपुर। अंग्रेजी हुकूमत के काल में छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शौर्य और बलिदान की स्मृति में नवा रायपुर, अटल नगर में निर्मित किए जा रहे भव्य संग्रहालय-सह-स्मारक को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी राज्योत्सव के अवसर पर इस संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। मुख्य सचिव श्री विकास शील ने आज निर्माण स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर बनाया जा रहा यह संग्रहालय देश का पहला पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय होगा। इसमें स्वतंत्रता आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में हुए 14 प्रमुख आदिवासी विद्रोहों के साथ-साथ जंगल सत्याग्रह और झंडा सत्याग्रह पर अलग-अलग गैलरियाँ बनाई जा रही हैं। संग्रहालय में आगंतुकों को इन जनजातीय आंदोलनों की जीवंत झलकें देखने और सुनने को मिलेंगी।निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव श्री शील ने कहा कि संग्रहालय में प्रदर्शित की जाने वाली सभी वस्तुओं और सामग्री को उनके मूल स्वरूप में ही प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि ओरिएंटेशन रूम में प्रदर्शित की जाने वाली डाक्यूड्रामा हल्बी-गोंडी या अन्य जनजातीय बोलियों में तैयार की जाए, ताकि यह स्थानीय संस्कृति से जुड़ाव का सशक्त माध्यम बन सके। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सभी गैलरियों का भ्रमण किया और आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने संग्रहालय में प्रदर्शित किए जाने वाले आदिवासी विद्रोहों का संक्षिप्त परिचय देते हुए पूरे रूट चार्ट के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने आज ही संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर लोकार्पण की तैयारियों की समीक्षा की। श्री बोरा ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण अवसर है कि देश का पहला पूर्णतः डिजिटल आदिवासी संग्रहालय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कर-कमलों से लोकार्पित होने जा रहा है। उन्होंने सभी विभागों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का आग्रह किया।प्रमुख सचिव श्री बोरा ने प्रधानमंत्री जी के लोकार्पण रूट-प्लान के अनुसार अनिवार्य सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने, संग्रहालय तक आने वाले पूरे मार्ग पर स्ट्रीट लाइट, रंग-रोगन एवं सौंदर्यीकरण के कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संग्रहालय क्षेत्र में चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा गार्डनिंग और वृक्षारोपण की आवश्यक तैयारियाँ भी समय पर पूरी हों।उल्लेखनीय है कि शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय देश का पहला पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय होगा। इसमें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में हुए प्रमुख आदिवासी विद्रोहों–हल्बा विद्रोह, सरगुजा विद्रोह, भोपालपट्टनम विद्रोह, परलकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, मेरिया विद्रोह, मुरिया विद्रोह, रानी चौरिस विद्रोह, भूमकाल विद्रोह, सोनाखान विद्रोह, तथा झंडा सत्याग्रह और जंगल सत्याग्रह–के वीर नायकों के संघर्ष और शौर्य को 14 गैलरियों में जीवंत रूप से प्रदर्शित किया जा रहा है।बैठक में संभागायुक्त श्री महादेव कावरे, आयुक्त आदिम जाति विकास विभाग डॉ. सारांश मित्तर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आयुक्त श्री अवनीश शरण, कलेक्टर श्री गौरव सिंह, नगर निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वजीत, संचालक टीआरटीआई श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, संचालक अंत्यावसायी विकास निगम डॉ. जगदीश कुमार सोनकर, अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती नम्रता जैन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेंद सिंह, डीआईजी छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं श्री सुरेश ठाकुर, एनआरडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के मुख्य अभियंता, तथा लोक निर्माण विभाग रायपुर के मुख्य और कार्यपालन अभियंता सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

गुणवत्ता और मानक ही आत्मनिर्भर भारत की पहचानः मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

विश्व मानक दिवस पर मुख्यमंत्री ने दिलाई गुणवत्ता शपथ, कहा – हर क्षेत्र में पारदर्शिता, उपभोक्ता अधिकार और नवाचार सर्वोपरि

विश्व मानक दिवस के अवसर पर आयोजित मानक महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में मानकों का पालन पारदर्शिता, गुणवत्ता और उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा वस्तुओं को मानक चिन्ह प्रदान कर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा रही है और इसके माध्यम से मिलावट व नकली वस्तुओं के कारोबार पर प्रभावी रोक लगी है।

मुख्यमंत्री श्री साय आज राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में विश्व मानक दिवस के अवसर पर आयोजित मानक महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने उपस्थित जनों को गुणवत्ता शपथ दिलाते हुए मानकीकृत उत्पादों को बढ़ावा देने और बीआईएस के प्रयासों में भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मानकों की स्थापना में विशेष योगदान देने वाले मानक क्लबों, संस्थाओं और मेंटर्स का सम्मान किया। उन्होंने भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था देशभर में गुणवत्ता की संस्कृति विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि एक समय था जब सोने जैसी धातुओं की शुद्धता का पता लगाना कठिन था, लेकिन आज हर उपभोक्ता बीआईएस हॉलमार्क देखकर ही आभूषण खरीदता है। बीआईएस का हॉलमार्क अब उपभोक्ता भरोसे का प्रतीक बन चुका है।

उन्होंने बताया कि बीआईएस द्वारा बोतलबंद पानी, हेलमेट, खिलौने, गहनों से लेकर करीब 22 हजार वस्तुओं को मानक चिन्ह प्रदान किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं के बीच मानक चिन्हों के प्रति जागरूकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को बढ़ावा मिल सके।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मानकों की अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता और मानकीकरण के कारण आज देश के गांव और कस्बों में बने उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान बना रहे हैं।मुख्यमंत्री श्री साय ने उपस्थित जनों से मानक चिन्हों के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि ÷विकसित भारत का संकल्प उपभोक्ता अधिकारों की मजबूती से ही पूरा होगा।÷ उन्होंने कहा कि गुणवत्ता ही आत्मनिर्भर भारत की वास्तविक पहचान है।कार्यक्रम में खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल ने कहा कि विश्व मानक दिवस का उद्देश्य उपभोक्ताओं और समाज में मानकीकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

यह हमारे वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों के प्रयासों को सराहने का अवसर भी है। उन्होंने कहा कि देश तेजी से विकास कर रहा है और गुणवत्ता सुधार अब केवल नीति नहीं, बल्कि एक संकल्प बन चुका है।श्री बघेल ने कहा कि ÷जागो ग्राहक जागो÷ का संदेश उपभोक्ताओं को सजग और जागरूक रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे इस कार्यशाला से प्राप्त ज्ञान को समाज में आगे बढ़ाएं, ताकि उपभोक्ता संरक्षण और अधिक सशक्त हो सके।

भारतीय मानक ब्यूरो रायपुर शाखा कार्यालय के निदेशक श्री एस. के. गुप्ता ने कहा कि बीआईएस का प्रत्येक मानक उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा को समर्पित है। उन्होंने बताया कि उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और ब्यूरो इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। श्री गुप्ता ने ब्यूरो द्वारा संचालित गतिविधियों और विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीआईएस का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में निर्मित हर उत्पाद वैश्विक गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरे।विश्व मानक दिवस के अवसर पर आयोजित मानक महोत्सव में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) तथा अन्य संस्थानों द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टालों का अवलोकन किया। उन्होंने मानक स्थापना से जुड़ी गतिविधियों और संस्थाओं की कार्यप्रणाली की जानकारी ली और उनके प्रयासों की सराहना की।

उठाईगीरी : अज्ञात चोरों ने बैग से उड़ाए 90 लाख रुपये और सोने-चांदी के जेवरात

बिलासपुर। जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में बीते रात एक बड़ी उठाईगिरी की वारदात सामने आई। अंबिकापुर निवासी सराफा व्यापारी किशोर कुमार को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने उनके बैग से करीब 90 लाख रुपये नकद और सोनेङ्कचांदी के जेवरात चोरी कर लिए। घटना की सूचना मिलते ही रतनपुर पुलिस ने तुरंत अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार, किशोर कुमार अपने व्यवसायिक काम के सिलसिले में अंबिकापुर से रायपुर जा रहे थे। वह रॉयल ट्रैवल्स की बस में सफर कर रहे थे। व्यापारी के अनुसार, बस रतनपुर क्षेत्र से गुजर रही थी, तभी अज्ञात आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से उनका बैग निशाना बनाते हुए नकदी और जेवरात पार कर दिए। घटना का खुलासा तब हुआ जब बस रायपुर पहुंची। अपने सामान की जांच के दौरान किशोर कुमार को चोरी का पता चला। इसके तुरंत बाद व्यापारी रतनपुर थाना पहुंचे और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने बस के ड्राइवर, क्लीनर और स्टाफ से पूछताछ की है और बस में सफर करने वाले अन्य यात्रियों की सूची भी जुटाई जा रही है। पुलिस का मानना है कि आरोपी यात्री बनकर बस में सवार हुए थे और किसी एक स्टॉप पर उतर गए। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस अब बस के सभी स्टॉपेज और मुख्य मार्गों की पड़ताल कर रही है।

नवा रायपुर में निवेश और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा, वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक

रायपुर। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में आज वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी की अध्यक्षता में निवेश, अधोसंरचना विकास और जनसुविधाओं से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई।

बैठक में मंत्री श्री चौधरी ने अधिकारियों से शहर के योजनाबद्ध और तीव्र विकास पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि नवा रायपुर का संतुलित, आधुनिक और सर्वसुविधायुक्त विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि चल रही परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए, ताकि नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें। उन्होंने बताया कि विकास कार्यों में गति लाने के लिए इस वर्ष राज्य शासन के बजट अंतर्गत पूंजीगत व्यय का लक्ष्य 1000 करोड़ रुपए रखा गया है। सभी इस लक्ष्य को गुणवत्तापूर्वक पूरा करने के लिए समर्पण भाव से कार्य करें।

मंत्री श्री चौधरी ने यह भी निर्देश दिए कि शासकीय एवं निजी संस्थानों तथा बिल्डर्स को आवंटित भूमि पर हो रहे निर्माण कार्यों को समन्वयपूर्वक और शीघ्र गति से पूरा किया जाए, ताकि नवा रायपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। बैठक में निवेश को प्रोत्साहन देने, पर्यावरण संरक्षण, अधोसंरचना विकास और शहरी जनसुविधाओं के उन्नयन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

इस अवसर पर प्राधिकरण के चेयरमैन श्री अंकित आनंद, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री चंदन कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

संरक्षा के सजग प्रहरियों को महाप्रबंधक, तरुण प्रकाश ने सम्मानित किया

बिलासपुर। रेल परिचालन में संरक्षा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है । सजगता एवं बेहतर संरक्षा कार्य में सहभागिता निभाने वाले रेल संरक्षा के सजग प्रहरी कर्मचारियों का सम्मान महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा हर माह आयोजित संरक्षा बैठक के दौरान किया जाता है । इसी कड़ी में आज दिनांक 14 अक्टूबर '2025 को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में कार्यरत संरक्षा कोटि के 04 कर्मचारियो को उनके उत्कृष्ट एवं सराहनीय संरक्षा सबंधी कार्य निष्पादन के लिए महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश के द्वारा सम्मानित किया गया बिलासपुर रेल मण्डल के यातायात सहायक-। / खोंगसरा, श्री थानेन्द्र दास ने दिनांक 23 सितम्बर, 2025 को अपने ड्यूटी के दौरान सुपर लॉन्ग हॉल को सिग्नल आदान-प्रदान के समय 2ठुस्र पार्ट के लोको व्हील में हैवी ब्रेक बाइंडिंग देख कर इन्होने लाल सिग्नल दिखाकर गाड़ी को खड़ी करवाया और तत्काल इसकी सूचना सर्वसंबंधित को दी । तत्पश्चयात, आगे की कार्यवाही कर ट्रेन को सूरक्षित रवाना किया गया । इस प्रकार श्री थानेन्द्र दास की सजगता एवं सतर्कता से ट्रेन परिचालन में संरक्षा सुनिश्चित हुई। बिलासपुर रेल मण्डल के सहायक लोको पायलट /बिलासपुर, श्री सैय्यद इकबाल तलहा ने दिनांक 17 सितम्बर, 2025 को अपने ड्यूटी के दौरान नर्मदा एक्स्प्रेस (ट्रेन नं.-18234) के इंजिन का सेकेंडरी हेलिकल स्प्रिंग प्रभावित देख कर इन्होने तत्काल इसकी सूचना सर्वसंबंधित को दिया । तत्पश्चयात, आगे की कार्यवाही कर ट्रेन को सूरक्षित रवाना किया गया । इस प्रकार सैय्यद इकबाल तलहा की सजगता एवं सतर्कता से ट्रेन परिचालन में संरक्षा सुनिश्चित हुई । रायपुर रेल मण्डल के ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-2 / सरोना, दशरथ लाल ने दिनांक 18 अगस्त, 2025 को अपने ड्यूटी के दौरान सरोना यार्ड/ सेक्शन में कि.मी. 835/26-28 के बीच मिडिल लाईन में रेलवे ट्रैक पर एक वेल्ड क्रैक देख कर, इन्होने तत्काल इसकी सूचना सर्वसंबंधित को दिया । तत्पश्चयात, आगे की कार्यवाही कर सुरक्षित रेल यातायात हेतु ट्रैक को ठीक किया गया । इस प्रकार दशरथ लाल की सजगता एवं सतर्कता से ट्रेन परिचालन में संरक्षा सुनिश्चित हुई । रायपुर रेल मण्डल के ट्रैक मैन्टेनर-2/आर. व्ही. एच, राधेश्याम ने दिनांक 14 अगस्त, 2025 को अपने ड्यूटी के दौरान रायपुर-मंदिर हसौद के बीच डाउन लाइन में किमी 7/6-8 के बीच बारिश के दौरान रेलवे ट्रैक वास आउट होने के कारण वहाँ एक गड्ढा को देखा और तत्काल इसकी सूचना सर्वसंबंधित को दी गयी ।

एकता, विकास और सांस्कृतिक गौरव का संदेश देगा छत्तीसगढ़ की झांकी का प्रदर्शन

एकता परेड-2025 में छत्तीसगढ़ की झांकी का हुआ चयन – मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दी बधाई

रायपुर। राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्टूबर) के अवसर पर गुजरात के एकता नगर (स्टैच्यू ऑफ यूनिटी) में आयोजित होने वाली एकता परेड-2025 में छत्तीसगढ़ राज्य की झांकी का चयन किया गया है। यह जानकारी भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची में दी गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के साथ जम्मू-कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर, उत्तराखंड, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, एनडीआरएफ और एनएसजी की झांकियाँ भी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के जनसम्पर्क विभाग की पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह चयन छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता, लोक परंपरा और एकता के भाव की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है। एकता परेड में प्रस्तुत होने वाली यह झांकी हमारे राज्य की 'एकता में विविधता' की अद्भुत परंपरा को सजीव रूप में प्रदर्शित करेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की झांकी इस वर्ष बस्तर की बदलती पहचान और विकास यात्रा पर केंद्रित होगी। राज्य शासन के जनसम्पर्क विभाग द्वारा तैयार की जा रही यह झांकी बस्तर की जनजातीय अस्मिता, पारंपरिक लोकनृत्य, वेशभूषा, ढोकरा धातु कला, आदिवासी चित्रकला और आधुनिक विकास के समन्वय को प्रदर्शित करेगी। झांकी का मुख्य संदेश होगा कि बस्तर अब बदलाव की राह पर है – संघर्ष से विकास की ओर, भय से विश्वास की ओर। इसमें दर्शाया जाएगा कि जिस भूमि ने कभी संघर्ष और असमानता के दौर देखे, आज वही क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और बुनियादी ढांचे के माध्यम से शांति और समृद्धि की नई पहचान गढ़ रहा है। राज्य सरकार की पुनर्वास एवं विकासोन्मुख नीतियों ने नक्सल प्रभावित इलाकों में स्थायी परिवर्तन की दिशा में नई ऊर्जा का संचार किया है। यह झांकी न केवल बस्तर की सांस्कृतिक आत्मा को प्रदर्शित करेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ के समग्र विकास, एकता और लोकगौरव की झलक भी पेश करेगी। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित इस भव्य परेड में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह स्वयं उपस्थित रहेंगे।

तनाव–मुक्त जीवन शैली पर प्रेरणादायक कार्यशाला का सफल आयोजन

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के एन. ई. इंस्टीट्यूट में आज दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को तनाव-मुक्त जीवन शैली विषय पर एक प्रेरणादायक कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया । इस कार्यशाला का उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य, संतुलित जीवन शैली तथा सकारात्मक सोच के महत्व से अवगत कराना था। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक प्रवीण पाण्डेय जी के करकमलों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं उद्घाटन संबोधन से हुआ । अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि–आज की तेज़ रफ़्तार जीवनशैली में तनाव एक सामान्य चुनौती बन गई है, परंतु योग, ध्यान, नियमित व्यायाम और समय प्रबंधन के माध्यम से इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। कार्यशाला में के रूप में वैद्य प्रोफेसर कृष्णा शर्मा (खंडेल), प्रजापिता ब्रह्माकुमारी संस्थान से बी. के. स्वाती दीदी तथा रेलवे के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. सुमित प्रकाश उपस्थित रहे । सभी वक्ताओं ने तनाव के कारणों, उसके दुष्प्रभावों तथा तनाव-मुक्त जीवन के लिए व्यावहारिक उपायों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। बी. के. स्वाती दीदी ने सकारात्मक चिंतन, आत्म-संवाद और ध्यान के माध्यम से मन की शांति प्राप्त करने के उपाय बताए। मुख्य वक्ता वैद्य प्रोफेसर कृष्णा शर्मा जी ने शरीर और मन के समन्वय हेतु योग एवं प्राणायाम की महत्ता पर प्रकाश डाला। डॉ. सुमित प्रकाश जी ने आधुनिक जीवन में मानसिक स्वास्थ्य की भूमिका पर उपयोगी सुझाव दिए और तनाव प्रबंधन के वैज्ञानिक पहलुओं को सरल रूप में समझाया। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों ने ध्यान, श्वास-प्रश्वास तकनीक एवं योगासन का व्यावहारिक अभ्यास भी किया। सभी प्रतिभागियों ने कार्यक्रम को अत्यंत लाभदायक एवं प्रेरणादायक बताया। अंत में उपस्थित सभी वक्ताओं एवं प्रतिभागियों के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला का समापन किया गया।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा अस्मा पब्लिशर्स इण्डिया प्राईवेट लि.,जयस्तंभ चौक, रायपुर से मुद्रित कर तथा 5/756 रामसागरपारा, सिंधी स्कूल के पीछे, स्टेशनरी हाऊस, रायपुर 492001 (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक प्रेमेन्द्र अग्रवाल ।
www.lokshakti.in, lokshaktidaily@gmail.com, twitter.com/lokshaktidaily, facebook.com/lokshaktidaily कार्यकारी संपादक : राजेश अग्रवाल (किसी भी विवाद पर न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा)